भारतीय कानून रिपोर्ट

समक्ष कुलवंत सिंह तिवाणा और एमएम पुंछी जे.जे.

न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर- याचिकाकर्ता

बनाम

कॉमरेड राम पियारा- प्रतिवादी

आपराधिक मूल अवमानना याचिका 7 वर्ष 1979

14 अगस्त 1981

न्यायालय की अवमानना अधिनियम (एल एक्स एक्स 1971) - धारा 2 (सी) और 6 - आपराधिक अवमानना - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों और साथ ही भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को संचार को संबोधित करने वाला अवमाननाकर्ता - 'उसमें इस्तेमाल की गई भाषा अत्यधिक अपमानजनक, अपमानजनक और व्यंग्यात्मक, बदनाम करने वाली, आलोचना करने वाली है और न्यायिक रूप से लिए गए निर्णयों के लिए मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के आचरण को बदनाम करने वाली है। प्रशासनिक रूप से - इस तरह के संचार - क्या यह प्रकाशन योग्य और दंडनीय है - अदालत अपने स्वयं के प्रस्ताव पर नोटिस जारी कर रही है - आरोप का औपचारिक निर्धारण - यदि आवश्यक हो - प्रशासनिक पक्ष में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की आलोचना - क्या यह आपराधिक अवमानना हो सकती है - अवमाननाकर्ता का दावा संविधान द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता- ऐसे अधिकार की सीमा।

आयोजित, कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 6 का उद्देश्य इसकी भाषा से स्पष्ट है। यह उन न्यायालयों से संबंधित है जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं लेकिन उच्च न्यायालय के नहीं। धारा 6 के खंड (ए)

के तहत जिला और सत्र न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं और इस प्रावधान का खंड (बी) उच्च न्यायालय का विशेष उल्लेख करता है। इसमें उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, जो अभिलेख न्यायालय है और इसकी उत्पत्ति संविधान से हुई है, जहाँ से इसकी शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। धारा 6 उच्च न्यायालय पर किसी भी एजेंसी या अदालत की पर्यवेक्षी शक्तियों की बात नहीं करती है और इस मामले में अवमाननाकर्ता द्वारा अपने कार्यों के लिए सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है। यह धारणा कि भारत के राष्ट्रपति/प्रधान मंत्री को संबोधित संचार के आधार पर अवमाननाकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, अत्यधिक गलत है। यह तर्क कि किसी प्रकाशन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि संचार मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को संबोधित किया गया था, समान रूप से बिना किसी आधार के है। मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबोधित किसी भी संचार को फाड़ा या फेंका नहीं जा सकता। इसे उच्च न्यायालय में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों को संरक्षित करने और रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए दिया जाना चाहिए। इस प्रकार आवश्यक रूप से ऐसे संचार उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड कार्यालय में जाने चाहिए और भले ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी हो, इन्हें रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, अधीक्षक आदि सहित कर्मचारियों को पारित करना होगा और इन का फाइलों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया, जिसे टाला नहीं जा सकता, इस तथ्य की परवाह किए बिना होनी चाहिए कि क्या सामग्री अपमानजनक, निंदनीय, अपमानजनक आदि है और यह पर्याप्त प्रकाशन के बराबर है, जैसा कि न्यायालय की अवमानना, बदनामी या किसी भी तरह से बदनाम करने के लिए अवमानना के कानून द्वारा किया गया है।

(पैरा 20)

आयोजित, अवमाननाकर्ता द्वारा उठाई गई यह आपत्ति गलत है कि यदि उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का कोई आरोप तय नहीं किया गया है या उसे बताया नहीं गया है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है। यदि आरोप तय करने का मतलब आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आरोप तय करना है, तो वह गलत धारणा के तहत है। यह अधिनियम अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है। यह अपराध का संज्ञान लेने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करता है। धारा 14 के तहत यह

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने किए गए अपराधों का संज्ञान लेने और उनसे निपटने और निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह अपील दायर करने की अपनी प्रक्रिया निर्धारित करता है और अपराध का संज्ञान लेने के लिए अपनी स्वयं की सीमा अवधि निर्धारित करता है। धारा 23 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को इसकी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले के लिए अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने वाले नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है और इस न्यायालय ने स्व-निहित नियम बनाए हैं, जो वैधानिक हैं। अधिनियम या नियम कहीं भी आरोप शब्द को परिभाषित नहीं करते हैं। अधिनियम के तहत, नोटिस में बताए गए आरोप या जिस सामग्री के आधार पर इसे जारी किया गया है, उसे आरोप के रूप में माना जाएगा। जैसे ही किसी अवमाननाकर्ता को नोटिस भेजा जाता है, आरोप का आरोप बता दिया जाता है। यह एक तरह से धारा 14(1)(ए) से परिलक्षित होता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उनके सामने अपराध करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है और उसे उस अवमानना के बारे में लिखित रूप से सूचित कर सकता है जिसके साथ उसने अपराध का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, उन्होंने इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय किए गए आरोप के बराबर नहीं माना जा सकता है। नोटिस के आधार पर लगाए गए आरोप और प्रत्येक संचार में चिह्नित अलग-अलग हिस्सों को अवमाननाकर्ता द्वारा अच्छी तरह से समझा जाता है और यदि अवमानना नोटिस में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, तो अवमाननाकर्ता यह नहीं कह सकता है कि आरोप नहीं बताया गया था या अनुचित तरीके से कहा गया था। उसे इस तरह से कि उसके साथ कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हो।

(पैरा 22)

आयोजित, आलोचना की कि प्रशासनिक पक्ष में उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 2(सी) में परिभाषित 'आपराधिक अवमानना' की श्रेणी में आता है। जबकि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या गैर-न्यायनिर्णय संबंधी मामलों पर भी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले न्यायाधीश की निंदात्मक आलोचना आपराधिक अवमानना के समान है। अवमाननाकर्ता द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी आलोचना यदि ऐसी भाषा में हो जो असंयमित हो, तो वह 'आपराधिक अवमानना' के दायरे में नहीं आ सकती।

(पैरा 26)

आयोजित, कि बेंचों के गठन के मामले में, मुख्य न्यायाधीश कानून द्वारा उन्हें दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने अधिकार का निर्वहन करते हैं, उन्हें न्याय प्रशासन के संबंध में एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के विशाल प्रतिष्ठान का प्रशासन एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर चलाता है। संविधान के अनुच्छेद 225/229 के तहत उनके कार्य पर डिस्चार्ज करने के लिए। उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष तक बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग केवल मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा किया गया था। किसी को भी मुख्य न्यायाधीश द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन की बदनामी के लिए उद्देश्यों या पूर्वाग्रहों को जिम्मेदार ठहराते हुए अनुचित और अनुचित आलोचना करने का अधिकार नहीं है, जो वह न्याय प्रशासन में अपना कर्तव्य निभाते हैं। यदि किसी न्यायाधीश की न्यायिक कार्यों के निर्वहन में उसकी सत्यनिष्ठा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी का उद्देश्य किसी न्यायालय को बदनाम करना या उसके अधिकार को कम करना है, तो यह आपराधिक अवमानना के समान है। जब इस तरह का कोई भी हमला या आलोचना न्याय के प्रशासन में पूर्वाग्रह पैदा करती है, हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप करती है या बाधा डालती है तो यह भी आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आता है। अधिनियम में प्रयुक्त 'स्कैंडलाइज़' शब्द का कोई विशेष या तकनीकी अर्थ नहीं है। इसके सामान्य अर्थ जो आमतौर पर समझे जाते हैं, उन्हें अधिनियम की धारा 2(सी)(आई) के संदर्भ में ध्यान में रखना होगा।

(पैरा 27, 28, 29 और 30)

आयोजित, हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन असीमित सीमा तक नहीं। लोगों को न्याय प्रशासन में न्यायाधीशों की आलोचना करने का सुरक्षित अधिकार है, लेकिन यह रचनात्मक होना चाहिए। आलोचना बेलगाम और अनियंत्रित नहीं हो सकती। न्यायाधीशों की आलोचना करने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शालीनता की सीमा के भीतर होनी चाहिए, इन सीमाओं को पार नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई न्यायाधीश द्वारा सदियों से पारित और समय-समय पर प्रतिपादित कानून द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाओं का उल्लंघन या अतिक्रमण करता है। विभिन्न देशों की सर्वोच्च अदालतों द्वारा

समय, फिर अदालतों को इसकी जाँच के लिए कदम उठाना पड़ता है। अवमानना कानून की सामान्य नीति यह है कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने की दिशा में कदम अनिच्छुक होना चाहिए और इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग झिझक के साथ किया जाना चाहिए। अभद्रता या अनुचितता के थोड़े स्वर वाली टिप्पणियों को न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत अपमान नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें केवल तभी टिप्पणियों पर ध्यान देना होता है जब वे न्याय के प्रशासन के संबंध में अपनी न्यायिक क्षमता में न्यायाधीशों के बारे में की जाती हैं और ऐसी होती हैं जो अदालतों को बदनाम करती हैं या पक्षपात करती हैं या न्याय प्रशासन या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करती हैं और ऐसी होती हैं इसे उन न्यायाधीशों द्वारा बर्दाश्त या समर्थित नहीं किया जा सकता है, जो स्वभाव से शांत हैं और अपने पद के कारण संयम और ईमानदारी के मामले में अनुभवी हैं। न्यायाधीशों की गरिमा की अतिरंजित धारणा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। न्यायालय की अवमानना के माध्यम से किसी कार्रवाई का सहारा तभी लिया जाना चाहिए जब उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीशों के अधिकार पर ज़बरदस्त हमला किया जाता है ताकि न्याय प्रशासन में जिम्मेदारी रखने वाली इस संस्था के अधिकार को कमजोर किया जा सके या इसमें हस्तक्षेप किया जा सके। उसके अधिकार को बदनाम करना या कम करना। यह सुनना कभी सुखद नहीं होता कि एक न्यायाधीश के खिलाफ निंदात्मक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अपशब्दों और आक्षेपों का प्रयोग किया गया। न्यायाधीश, जो मानव हैं, को ऐसे मामलों की सुनवाई करते समय अवमाननाकर्ता के सामने शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखना होता है, जो बहस के दौरान कई बार अपने द्वारा लिखे या मुद्रित मामले की तुलना में अधिक जोश और व्यंग्य के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। अपने आप पर या जिस संस्था से वह जुड़ा है उसके बारे में मानहानि का पाठ पढ़ने और उसे अदालत में न्यायाधीश के सामने बार-बार सुनने में हमेशा अंतर होता है।

(पैरा 31)

पूर्व एम.एल.ए. कॉमरेड राम पियारा पूर्व के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971, (1971 का अधिनियम संख्या 70) के तहत माननीय श्री न्यायमूर्ति हरबंस लाल और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. दीवान की खंडपीठ के आदेश के तहत 19 मार्च, 1979 को करनाल में न्यायालय द्वारा कार्यवाही

प्रारंभ की गई।

यू. डी. गौड़, ए. जी. हरियाणा- याचिकाकर्ता के लिए।

राम पियारा कॉमरेड साक्षात्।

निर्णय

केएस तिवाना, जे.

(1) कैसे गलत जिद वाले वादी, शातिर जुबान वाले, दबंग रवैया अपनाकर उच्च न्यायालय सहित न्यायालयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और उन पर अपनी बात मानने और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं, इसका उदाहरण राम पियारा द्वारा दिया गया है। साथी। उनके आचरण और रवैये के कारण इस न्यायालय ने अपने प्रस्ताव पर, उनके आचरण को दंडित करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की। श्री राम पियारा, जिनके पास अपराध में इस न्यायालय में इस तरह की कार्यवाही का पूर्व अनुभव था, अर्थात न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत! 1971 की मूल संख्या 257 और 259 को ***कोर्ट ऑन इट्स मोशन* बनाम *राम पियारा कॉमरेड***[1] के रूप में रिपोर्ट किया गया, इस मामले में प्रतिवादी है। यद्यपि 1971 की आपराधिक मूल संख्या 257 और 259 में श्री राम पियारा के खिलाफ नियम को खारिज कर दिया गया था, कोर्ट ने उनके बारे में इन शब्दों में कहा: -

> "मुझे संदेह है, प्रतिवादी, जैसा कि हम उसके तर्कों और मुख्य न्यायाधीश को संबोधित पत्रों में उसके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा के चलन से समझ पाए हैं, एक अभिमानी व्यक्ति है जिसे अपने खिलाफ अपमानजनक हमले करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कोई भी व्यक्ति उसके रास्ते में

[1] 1973 क्रिमिनल एल. जे. 1106।

आता है।"

क्या एक दशक बीतने के बाद उनमें बेहतरी के लिए कोई बदलाव आया है?

2. प्रतिवादी ने श्री बंसी लाल , मुख्यमंत्री, हरियाणा, श्री सुखदेव पार्षद, आईएएस और श्री एसके सेठी, आईएएस, जिन्हें श्री एनएल द्वारा उनकी शिकायत पर तलब नहीं किया गया था, के आरोपमुक्त करने के खिलाफ इस न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444/1978 दायर किया था। प्रूथी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल। जैसा कि एसएस संधवालिया, सीजे को संबोधित उनके विभिन्न पत्रों और संचारों से पता चलता है, वह चाहते थे कि उक्त आपराधिक पुनरीक्षण की सुनवाई एकल पीठ द्वारा नहीं बल्कि पांच न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ द्वारा की जाए। *'एसएस संधावालिया, सीजे, न्यायाधीश के रूप में, और एससी मितल, जे.,* जिनके समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण। 1978 के नंबर 444 को व्यक्तिगत रूप से सूचीबद्ध किया गया था और इस पर सुनवाई न करने का फैसला किया था और इसे किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। प्रशासनिक पक्ष से मुख्य न्यायाधीश एसएस संधावालिया ने उच्च न्यायालय में सेवारत अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी थी। प्रतिवादी ने इन मामलों के बारे में मुख्य न्यायाधीश को लिखना शुरू कर दिया और एक न्यायिक अधिकारी श्री आरएल लांबा के मामले के बारे में भी, जिन्हें उच्च न्यायालय ने समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया था और जिनका नाम 1973 क्रिमिनल एल. जे. 1106 (सुप्रा) में आया था। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को लिखे गए इन पत्रों की भाषा, जो कि 11 आपराधिक मूल अवमानना मामलों का विषय है, पर इस न्यायालय की विभिन्न डिवीजन बेंचों द्वारा विचार किया गया था, जिसमें पाया गया कि यह न्यायालय को बदनाम करने जैसा है, और समाज की नजरों में उसकी गरिमा कम करें। विभिन्न खंडपीठों ने राम पियारा को अवमानना का नोटिस जारी किया। उन्होंने विशिष्ट भागों को चिह्नित किया, जो, उनके विचार में, कार्यवाही के दौरान अवमानना के समान थे लेकिन अन्यथा समग्र रूप से पत्रों की भाषा और भाव अत्यधिक प्रभावशाली थे।

3. शृंखला में पहला पत्र 4 नवंबर, 1978 तारीख़ का है जो 1979 की आपराधिक मूल अवमानना संख्या 7 का विषय है, जो प्रतिवादी राम पियारा द्वारा भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखा गया था, जिसकी प्रति इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक भी पहुंची थी। खंडपीठ द्वारा चिह्नित भाग 'ए' है: –

"चंडीगढ़ पहुंचने के बाद, जब मैंने पूछताछ की, तो मुझे पता चला कि यह मामला न्यायमूर्ति एससी मितल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिन्होंने पहले ही मई 1978 में सुनवाई से इनकार कर दिया था। मैं वास्तव में स्तब्ध था या मैं कह सकता हूं, चकित और चकित था, यह देखकर कि क्या मज़ाक है और वह भी माननीय सीजे श्री संधावालिया द्वारा, जिन्हें मेरे दोनों पत्रों में यह स्पष्ट किया गया था कि "तीन को छोड़कर बेंच का गठन किया जाए। जस्टिस संधावालिया, जस्टिस एससी मितल, जो पहले ही कह चुके हैं कि वे सुनवाई नहीं करना चाहते, और तीसरे जस्टिस जेएम टंडन, जो आवंटन के लिए शाह आयोग के समक्ष जांच का सामना कर रहे हैं। बंसी लाल , सुखदेव पार्षद द्वारा उन्हें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के माध्यम से उपायुक्त के रूप में अवैध रूप से आवंटित एक भूखंड का आवंटन किया गया था।"

'बी' चिह्नित दूसरा भाग पढ़ता है: -

> "क्या यह मेरी गलती या पाप है कि मैंने न्यायमूर्ति संधावालिया द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख को 58 से 60 तक लाकर संविधान के उल्लंघन की ओर इशारा किया है, जिससे न केवल संविधान का उल्लंघन हुआ है, न केवल रोजगार के कार्यक्रम में तोड़फोड़ हुई है, बल्कि श्री सत पॉल पार्टी, उनके सचिव के प्रति स्नेह/एहसान दिखाया गया।

यह इस उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से संबंधित है।

4. दूसरा पत्र जिसके लिए 1979 का सी. ओ. सी. स. _ शुरू किया गया है, वह दिनांक 2 दिसंबर, 1978 का है, जो राम पियारा द्वारा एसएस संधवालिया, सीजे को उनके आपराधिक पुनरीक्षण के संबंध में लिखा गया था, जिसमें श्री

केएस थापर उनके विरोधियों के वकील थे। इस पत्र में उन्होंने लिखा:

> “मैं उस संभ्रांत सोच पर सवाल उठाऊंगा जो हमेशा अमीरों, ताकतवरों और सफेदपोशों के पक्ष में होती है और यही बात हाई कोर्ट और के.एस. थापर के मूर्खतापूर्ण और नासमझी भरे कदम के लिए भी है। मुझ पर क्यों बोझ डाला गया है ?”

इसी सन्दर्भ में उन्होंने भाग 'बी' इस प्रकार लिखा: –

> "आप न्याय देने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि झूठी प्रतिष्ठा के कारण और आरोपियों की मदद करने के लिए, एक तरफ डायलैटरी रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी तरफ पूर्ण पीठ का गठन नहीं किया जा रहा है।"

उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में उन्होंने भाग 'सी' में इस भाषा का प्रयोग किया:

> “आप अकेले सतपाल पार्टी से प्रभावित क्यों हो गए, आपके सचिव? क्या आपका यह कृत्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है - क्या आपने संविधान का उल्लंघन नहीं किया है?”

इसी सन्दर्भ में उन्होंने भाग 'द' लिखा: –

> "लेकिन अप्राप्य होने का दावा करते हुए, हव्फ़ व्यक्तियों के दबाव का विरोध करने में विफल रहे और इस प्रकार न केवल बलिदान दिया राष्ट्रहित और बेरोजगारी की गंभीर समस्या के साथ-साथ संविधान का भी उल्लंघन किया है।”

इस न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का जिक्र करते हुए उन्होंने 'ई' अक्षर में इस भाषा का प्रयोग किया:

> “सीजे श्री हरबंस सिंह की ओर से यह बेहद अनुचित और बेहद निंदनीय था। क्या आपको न्यायपालिका में कहीं ऐसा मिला जहां अपने ही न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने ही मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मीठी, विनम्र टिप्पणियां की हों। फिर आप उस फैसले में पाएंगे कि जस्टिस महाजन ने भी जस्टिस हरबंस सिंह द्वारा पेश किए जाने वाले घृणित

नाटक में हाथ मिलाया था, क्योंकि जस्टिस महाजन को मुझसे द्वेष था, मैंने कभी-कभी एक शपथ पत्र दायर किया था जिसमें जस्टिस महाजन ने मेरी चुनाव याचिका में अपने न्यायालय के रिकॉर्ड' के साथ छेड़छाड़ की थी।

पूर्ण पीठ के समक्ष अपने आपराधिक पुनरीक्षण को सूचीबद्ध करने की अपनी मांग पर पलटवार करते हुए, उन्होंने इस पत्र में भाग 'एफ' में लिखा: -

"उपर्युक्त से कोई भी सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस समय तक, आपने भी मेरे प्रति द्वेष पा लिया है और यदि ऐसा नहीं होता, तो आपने विशेष रूप से सुनवाई के प्रति आपकी अनिच्छा और फिर मेरी आशंकाओं को देखते हुए पूर्ण पीठ का गठन कर दिया होता। ^ फिर गृह मंत्रालय को मेरी शिकायत यह बताती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का उनका दावा न्यायमूर्ति संधवालिया और न्यायमूर्ति एससी मित्तल के रुख से गलत साबित होता है और इसके अलावा आपके अविवेकपूर्ण, राष्ट्र-विरोधी और संविधान के उल्लंघन के खिलाफ मेरी शिकायत, संशोधन एक व्यक्ति और वह भी उसके लिए जिसकी प्रतिष्ठा निराशाजनक है और इसलिए, इन परिस्थितियों में, यह और भी अधिक अनिवार्य था कि बेंच का गठन किया गया होता। यह शायद मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप पर से अपना विश्वास खो रहा हूं और मेरे पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि आप किसी न किसी से बात कर सकते हैं और इसलिए पांच की खंडपीठ ने मांग की कि आप सभी को ध्वनि/संकेत देने में अक्षम हैं।

5. तीसरा पत्र 8 दिसंबर 1978 का है। श्री राम पियारा ने एसएस संधावालिया, सीजे को संबोधित किया है। अपने आपराधिक संशोधन का जिक्र करते हुए, उन्होंने भाग 'ए' लिखा: -

“यदि आपका आधिपत्य झूठी प्रतिष्ठा की आड़ में है, और अन्यथा भी मुझे चोट पहुँचाने और बचाने के इरादे से बंसी लाल, सुखदेव पार्षद, बेंच का गठन नहीं करने और मुझे निचोड़ने और थका देने

के प्रयास जारी रखने के लिए दृढ़ हैं, तो मेरे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।

भाग 'बी' में उन्होंने लिखा: –

"क़ानून तो ठीक है लेकिन योर लॉर्डशिप की मंशा ठीक नहीं है।" आपराधिक मूल अवमानना प्रकरण संख्या 9 इस संचार के संबंध में 1979 में पहल की गई थी।

6. 1979 का चौथा आपराधिक मूल अवमानना मामला संख्या 10, 8 जनवरी, 1979 के पत्र के आधार पर शुरू किया गया है, जिसे श्री राम पियारा ने अपने आपराधिक संशोधन के संदर्भ में एसएस संधावलिया, सीजे को फिर से संबोधित किया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था: –

> "चूँकि मैं बहुत ही सीमित साधनों वाला व्यक्ति हूँ और पूरे परिवार को कुछ प्रतिवादियों के हाथों भारी कष्ट सहना पड़ा है और फिर आपातकाल के दौरान भी कष्ट सहना पड़ा, इसलिए न्याय के मुद्दे पर भी मेरी अनदेखी की जा रही है, जबकि बंसी लाल, सुखदेव पार्षद जिन्होंने कमाया है बहुत से लोग भ्रष्ट हैं, गिरफ्तार किए गए हैं और जमानत पर छूट गए हैं, सुखदेव प्रसाद लंबे समय से निलंबित हैं और कई मामलों में दोषी ठहराए जाने की संभावना है, आपके आधिपत्य की नजर में और अनुमान है कि वे आपकी मित्रता और बहुत अधिक विचार के पात्र हैं। मुझे बहुत सारी ऊर्जा और समय की खपत के अलावा अनावश्यक खर्च करने के लिए मजबूर किया गया है, किसी साधारण कारण से कि वह किसी न किसी समय आपके लिए उपयोगी रहा होगा।

7. पांचवां आपराधिक मूल अवमानना 1979 का मामला क्रमांक 11 है। इसमें श्री राम पियारा द्वारा 24 जनवरी, 1979 को एसएस संधवालिया, सीजे को लिखे गए पत्र में प्रयुक्त भाषा के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई है। इसमें भाग 'ए' में इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश का संदर्भ दिया गया है: -

"इस तरह का रास्ता उनके द्वारा नहीं अपनाया गया था, लेकिन उच्च

न्यायालय ने, दंभपूर्ण तरीके से, एक भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के लिए अपने बुरे इरादों से स्वस्थ मिसालों को रौंद दिया, जो इस रिपोर्ट वाले फैसले (क्रिमिनल लॉ जर्नल 1973), पृष्ठ (1116) के लिए था। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों को दोषी ठहराया गया। उनके अपराध के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश श्री हरबंस सिंह को भी दोषी माना गया। उच्च न्यायालय के उप रजिस्ट्रार मुख्य न्यायाधीश श्री हरबंस सिंह और न्यायमूर्ति डीके महाजन की रुचि के कारण, जिनका नाम भी रिपोर्ट किए गए फैसले में शामिल है, सम्मान के साथ नहीं।

भाग 'बी' में उन्होंने लिखा:

"उसी तरीके से, मैं प्रशासनिक पक्ष से श्री न्यायमूर्ति एससी मितल द्वारा पारित आदेश की एक प्रति की मांग करने के लिए आवेदन करने का अनुरोध करता हूं, जिसमें उन्होंने डिवीजन बेंच द्वारा पारित किए गए सख्तों को मिटा दिया, जिसने अवमानना कार्यवाही शुरू की। सीजे हरबंस सिंह और जस्टिस डीके महाजन द्वारा मेरे खिलाफ, भ्रष्ट तरीके से और बहुत ही गलत तरीके से, सभी शालीनताओं को हवा में फेंक दिया गया क्योंकि एक तरफ भ्रष्ट लांबा का पक्ष लिया जाना था और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा को दंडित किया जाना था।

प्रशासनिक निर्णय के संबंध में, जो श्री राम पियारा के अनुसार, श्री आरएल लांबा के संबंध में प्रशासनिक पक्ष पर एससी मितल, जे द्वारा लिया गया था, उन्होंने भाग 'सी' में लिखा: -

"यह सुनने के बाद कि प्रशासनिक पक्ष के न्यायमूर्ति एस, सी. मितल ने न्यायिक पक्ष पर दिए गए पीठ के फैसले को खारिज कर दिया है, मुझे आश्चर्य हुआ और आश्वस्त हुआ कि इस उच्च न्यायालय में न्यायपालिका के मानकों में गिरावट आ रही है।"

8. इन सभी पांच मामलों में, यानी 1979 के सीओसी नंबर 7 से 11 तक, 19 मार्च, 1979 को नोटिस जारी किए गए थे। चूंकि कार्यालय ने बेंच के

निर्देशों के तहत, इन सभी मामलों में एक समग्र नोटिस जारी किया था, इसलिए अलग-अलग नोटिस जारी किए गए थे। 27 अप्रैल, 1979 को श्री राम पियारा प्रतिवादी को अवमानना के लिए आदेश जारी किए गए थे।

9. जबकि एसएस सिद्धू और हरबंस लाल, जेजे की एक डिवीजन बेंच सीआरएल का ढेर लगा रही थी। 1979 के ओसीपी नंबर, 7 से 11, प्रतिवादी ने उनसे पहले विविध क्रमांक 2700, दिनांक 24 मई 1979 दायर कर दी। इसमें उन्होंने भाग 'क' में लिखा: -

"प्रतिवादी को माननीय न्यायाधीशों से अधिक रोशनी की उम्मीद थी, लेकिन दुर्भाग्य से अधिक गर्मी आई - शायद माननीय सीजे श्री एस. एस. संधवालिया के संकेत ने कानूनी दायित्वों और अन्य की तुलना में अधिक महत्व दिया और अदालतों की गरिमा बनाए रखने के लिए स्वस्थ मिसालें कायम करें क्योंकि कानून का शासन एक निष्पक्ष, निडर और स्पष्टवादी न्यायपालिका के अस्तित्व पर निर्भर करता है।"

इन मामलों की सुनवाई कर रही बेंच ने 25 मई 1979 को नोटिस जारी किया और 1979 के सीआरपीसी क्रमांक 18 शुरू की।

10. श्री राम पियारा प्रतिवादी ने 2 अप्रैल 1979 को एसएस संधवालिया, सीजे को पत्र लिखा था, इसमें आपत्तिजनक अंश जिनके लिए नोटिस जारी किए गए थे: -

> "आप सुनवाई से इनकार करने वाले पहले व्यक्ति थे और स्वाभाविक रूप से, अन्य न्यायाधीशों को शायद यह संकेत मिल गया था कि न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया को किसी न किसी चीज़ में कुछ रुचि है।"
>
> * * * *
>
> “क्या यह न्याय है? मैं इस बात पर विश्वास करने से इनकार करता हूं बल्कि आपने मुझे यह आभास दिया है कि एक या दूसरे की मदद करने के लिए, आप स्वस्थ परंपराओं को कुचलने के प्रति बेपरवाह हो गए हैं।

मुझे यह देखने में कोई झिझक नहीं है कि मेरे भंडार में आपके प्रति जो भी थोड़ा बहुत विश्वास बचा था, वह आज हिल गया है, आपने संविधान द्वारा सौंपे गए अपने पवित्र कर्तव्यों का पालन करने के बजाय अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है और इस प्रकार इसकी प्रतिष्ठा को कम करने के न्यायिक मानक दोषी बन गए हैं।"

ये नोटिस 1979 के सीआरएल ओ. सी. ओ नंबर 19 में जारी किए गए थे।

11. प्रतिवादी ने 25 अप्रैल, 1 को फिर से एसएस संधावालिया, सीजे को पत्र लिखा, जिसके आधार पर सी.आर.एल. 1979 का ओसी नंबर 20 शुरू किया गया है। बेंच की राय में इसके बाद पुनरुत्पादित अंशों में टिप्पणियाँ न्यायालय को बदनाम करने वाली थीं और परिणामस्वरूप नोटिस जारी किया गया था: -

"यह पता चला कि डीबी द्वारा पारित सख्तियों को प्रशासनिक पक्ष के एकल न्यायाधीश (श्री एससी मित्तल) ने खारिज कर दिया था, जो कि अवैध, असंवैधानिक है और एक बहुत खराब मिसाल कायम करता है और कुछ अन्य लोग इस तरह का हवाला दे सकते हैं उदाहरण और इस तरह से. न्याय की शुचिता ख़राब हो सकती है।"

* * * *

मैं इसे जानबूझकर की गई शरारत मानता हूं, संभवतः किसी के पूछने पर, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी में ऐसा नहीं कर सकता था । मैं प्रसंगवश आपका ध्यान क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1973 पृष्ठ 1106 में छपे डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) की भूमिका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और संबंधित भाग इस प्रकार है:

डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने प्रतिवादी को संबोधित एक कार्यालय पत्र में कहा कि उन्हें गुरदेव सिंह और गोपाल सिंह, जेजे की माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पत्रों की प्रतियां अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया था। दिनांक 3 नवंबर, 1971, 26 नवंबर, 1971 और 30 नवंबर, 1971 को हरियाणा के राज्यपाल और माननीय मुख्य न्यायाधीश को संबोधित

और पत्र दिनांक 17 दिसंबर, 1971 भी संबोधित किया था। पीठ के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह कह सके। आश्वस्त रहें कि अन्य पत्रों की प्रतियां प्रतिवादी को प्रदान करने का इरादा नहीं था।

ऐसी शरारतें आम हैं जहां सीजे के इरादे ईमानदार नहीं हैं और इसलिए, यह सुरक्षित रूप से समझा जा सकता है कि पिछले की तरह, वर्तमान उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने आपकी इच्छा को लागू किया होगा।

“अब, यह मेरे संज्ञान में आया है कि श्रीमान न्यायमूर्ति एस. सी. मितल ने हरियाणा के पूर्व सीएम बंसी लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। भेदभाव क्यों? मेरे मामले में उन्होंने मना कर दिया लेकिन अब सुना। न्यायपालिका में दोहरे मानदंडों का लाभ देश को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। इसलिए, मैं इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उठाने के लिए इच्छुक हूं और इसके लिए श्री न्यायमूर्ति एस. सी. मितल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति, प्रशासनिक पक्ष पर सख्ती को धोते हुए, न्यायिक पक्ष पर डीबी द्वारा पारित की गई है, उसे मुझे दे दिया जाए। यह 24 जनवरी, 1979 की मेरी पिछली मांग के अनुसरण में है जिसमें एक अतिरिक्त आधार है कि न्यायमूर्ति एससी मितल ने बंसी लाल और सुखदेव पार्षद के खिलाफ मेरे पुनरीक्षण को क्यों अस्वीकार कर दिया और उन्होंने बंसी लाल की याचिका क्यों सुनी, अंतर अधिक स्पष्ट है। बंसी लाल भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त हैं जबकि मैं स्वयं पीड़ित हूं, मुझे दर-दर भटकना पड़ रहा है। यदि यह न्यायिक आदेश होता....."

12. पत्र दिनांक 19 मई, 1979 को श्री. श्री. पियारा द्वारा के. एस. तिवाना, जे. को संबोधित किया गया, जिस पर सी.ओ.सी. 1979 की संख्या 21 को एक डिवीजन बेंच के आदेश के तहत शुरू किया गया था। जो भाग हैं, सामग्री और बेंच द्वारा उन्हें नोटिस जारी करते समय इस प्रकार चिह्नित किया गया है: '-

"मैंने आपके आधिपत्य में, आपके आधिपत्य में विश्वास खो दिया है।

* * * * *

माननीय सीजे श्री एस. एस. संधावालिया के प्रभाव में काम किया, जो सबसे भ्रष्ट लोगों के हितों की निगरानी कर रहे हैं, श्री सुखदेव पार्षद, आईएएस, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कई मामलों और शक्तियों के दुरुपयोग के कारण लंबे समय से निलंबित हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर भारी रकम, सार्वजनिक धन हड़प लिया और कई घृणित गतिविधियों में शामिल हो गए। शायद अपनी गिरफ़्तारी से पहले भी उसे श्री एस.एस. संधावालिया की अनुचित मदद की गारंटी मिली हुई थी।

* * * * *

"मैं, कानून का पालन करने वाला हूं, और आपके आधिपत्य या माननीय सीजे श्री एसएस संधावालिया के रूप में, कम से कम अपने मामलों में कानून को रौंदने वाला नहीं हूं।

प्रतिलिपि: माननीय श्री एसएस संधावालिया, मुख्य न्यायाधीश और उपमिशन है कि वह न्यायपालिका के मानकों को गिराने का मूल कारण बन रहे हैं।"

13. प्रतिवादी ने 28 सितंबर 1979 को फिर से के. एस. तिवाना, जे. को पत्र लिखा, जिसके आधार पर न्यायालय की अवमानना करने के लिए 1979

का सीओसीएन 22 जारी किया गया था। आपत्तिजनक अंश आगे प्रस्तुत हैं: -

'ए' ".....और इसलिये तुम्हारे हाथ में न्याय की छड़ी सीधी नहीं है, और न्याय का तराजू सीधा नहीं है।"

* * * * *

'बी' श्री संधावालिया, सीजे की रुचि के कारण, केस फाइल को श्री सुखदेव पार्षद, बंसी लाल के लाभ के लिए व्यवस्था करने के लिए भेज दिया गया था।

* * * * *

'सी' श्री संधावालिया ने किसी अन्य पीठ का उल्लेख नहीं किया, जिसने पहले इनकार नहीं किया था क्योंकि केएस तिवाना न्यायाधीश, वे जानते थे, श्री सुखदेव पार्षद के क्लास-फेलो थे और सुखदेव पार्षद और बंसी लाल के हित को बेहतर ढंग से देख सकते थे।

* * * * *

'डी' लेकिन उसे सीजे संधावालिया का पालन करना था न कि स्वस्थ उदाहरणों का।'

* * * * *

'ई' श्री केएस तिवाना का आदेश न केवल दुर्बलताओं से भरा है, बल्कि दुर्भावना, धूर्तता, बल्कि बेईमानी से भरा है और इसलिए आपके दोनों आधिपत्य दुर्व्यवहार और कदाचार के दोषी हैं, जिसके लिए संसद द्वारा नहीं तो सर्वशक्तिमान द्वारा महाभियोग की आवश्यकता है।

* * * * *

'एफ'.....लेकिन आपने उन भ्रष्टों के प्रति स्नेह के कारण अन्यथा कार्य किया है जिनके पास इस न्यायालय में ट्रक हैं।

* * * * *

'जी' मैं देखता हूं कि आप दोनों द्वारा अधिकार का दुरुपयोग किया गया

है, मामले से सार, जीवन और आधार को हटाकर मेरी सीआर का फैसला किया गया है। अवशेषों पर संशोधन ने न केवल न्यायपालिका को प्रदूषित किया बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।

* * * * *

'एच' यह मेरी सुविचारित राय है कि यदि मैं आप दोनों को यह लिखने का साहस करूँ कि आप सबसे अधिक भ्रष्ट, पक्षपाती, अन्यायी हैं, तो आप बहुत नाराज़ होंगे।

* * * * *

वास्तव में आपने खुद को दोनों यानी बंसीलाल और सुखदेव पार्षद से भी अधिक भ्रष्ट, अधिक बेईमान साबित किया है। मेरा तुम्हें लिखने का उद्देश्य यह है कि तुम उन लोगों पर कहर न ढाओ जो पढ़-लिख नहीं सकते। मुझे पता है कि वकील (कुछ) पेय पेश कर सकते हैं और क्या नहीं और इसी तरह श्री सतपाल पार्टी, सीजे के सचिव श्री संधवालिया की उपयोगिता भी है, जिनके लिए वह संविधान जिसके वह संरक्षक हैं, का उल्लंघन किया गया है। और इस तरह से भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा मिला है।

* * * * *

'जे' मैं देखूंगा और आपके महाभियोग के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कष्टों की कीमत पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा क्योंकि आप दोनों ने न्यायमूर्ति एसएस सिद्धू और हरबंस लाल के साथ मिलकर काम किया है, जिनके आदेश भी न केवल मूर्खता पर बल्कि चालाकी पर भी आधारित हैं, क्योंकि वे श्री एसएस संधावालिया को बहुत अधिक परेशान नहीं कर सकते।

* * * * *

'संक्षेप में आने से पहले, मैं आने वाली पीढ़ियों के नाम पर आपसे अपील

करता हूं कि न्यायप्रिय बनें और न्यायपालिका को प्रदूषित करके और इस तरह समाज को भ्रष्ट करके भ्रष्ट न बनें।'

14. नोटिस सीओसी नंबर 23 ऑफ 1979, इस शृंखला में अंतिम, 14 जून 1979 के एक पत्र के आधार पर जारी किया गया, जो प्रतिवादी एसएस सिद्धू और हरबंस लाल, जेजे को संबोधित था, जिन्होंने इन मामलों में उसके खिलाफ की सुनवाई की थी। वे अंश, जो नोटिस जारी करने वाली पीठ की राय में, अदालत की अवमानना के समान हैं: -

'ए' ".....आपके आधिपत्य में श्री सीजे संधावालिया के कारणों को सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है, जो बुरे इरादों के साथ, मुझे हतोत्साहित करना चाहते हैं ताकि मैं उनकी गलतियों को उजागर न कर सकूं या अपनी पिछली शिकायतों पर ध्यान न दे सकूं, जिनमें से एक के खिलाफ मैंने विरोध किया था, संविधान के संरक्षक द्वारा संविधान का उल्लंघन था। महामहिम, यदि सराहना कर सकते हैं, तो कृपया सराहना करें जब सीजे श्री एसएस संधावालिया स्वयं संविधान का उल्लंघन करते हैं और वह भी एक व्यक्ति के लिए, इस प्रकार समाज की अनदेखी करते हैं तो फिर मैं संविधान की पवित्रता कहां है और मुख्य न्यायाधीश श्री संधावालिया की विश्वसनीयता कहां है। विश्वसनीय, सत्य से अधिक विश्वसनीय है। दुर्भाग्य यह है कि विरोध करने वालों की कमी है, अन्यथा उनकी पीठ पर, कई लोग इस बात पर जोर देते हैं कि सीजे श्री एस. एस. संधावालिया ने संविधान का उल्लंघन करके, श्री सतपाल पार्टी को बाध्य किया है, जिन्होंने खुद को शराब की आपूर्ति करने के लिए बाध्य किया है। सीजे श्री संधावालिया जनरल बहुत उपस्थित थे, उन्होंने विचार-विमर्श में भाग लिया लेकिन महामहिम, उन कारणों से जो आप ही जानते हैं, जानबूझकर उनकी

उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया। मेरा आशंकित होना स्वाभाविक था, विशेषकर सीजे श्री एसएस संधावालिया के दुर्व्यवहार को देखते हुए, जिन्होंने बेईमानी से कुछ कागजात वापस रख लिए। मेरे विरोध के बावजूद, आप दोनों ने सी. जे. श्री संधावालिया से यह नहीं कहा कि वे सभी कागजात अदालत के समक्ष शेष कागजात के रूप में उनके पास रखें। ये उसकी संपत्ति नहीं बल्कि न्यायालय की संपत्ति हैं। मेरे पास उन सभी दस्तावेजों की मांग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था जिनके बिना नोटिस के जवाब में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता था। लेकिन आपने शालीनता, न्याय, कानून की कम परवाह की बल्कि सीजे श्री संधावालिया की सनक और भनक की ज्यादा परवाह की। मैं आपका ध्यान इसी उच्च न्यायालय के क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1973, पृष्ठ 1106 में रिपोर्ट किए गए निर्णयों की ओर आकर्षित करना चाहता था, लेकिन आपने सुनने से इनकार कर दिया क्योंकि ऐसा न करते हुए, आपके आधिपत्य ने सीजे श्री संधावालिया के हित को देखा, न कि न्याय के।

* * * * *

'सी' इस बार आप सुनना नहीं चाहते क्योंकि ऐसा लगता है कि आप को सी जे संधावालिया जी से विशेष निर्देश मिला है।

* * * * *

'डी' दुर्भाग्य से मैंने सीजे की प्रामाणिकता पर से पूरी तरह विश्वास खो दिया है। श्री एसएस संधावालिया, जिन्होंने श्री सुखदेव पार्षद के रूप में अपनी कंपनी पाई, सबसे भ्रष्ट, शराबी और अय्याश थे और उनकी खातिर उन्होंने सभी स्वस्थ उदाहरणों और अच्छी परंपराओं को हवा में उड़ा दिया और इसलिए न्यायमूर्ति केएस तिवाना से श्री बंसी के

खिलाफ मेरे संशोधन पर बेईमानी से फैसला करने के लिए कहा। लाल, सुखदेव पार्षद और स्वयं सीजे श्री संधावालिया ने भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और इस स्थिति में, यदि वह बहुत नीचे गिर सकते हैं, तो वह उचित और अनुचित तरीकों से मुझे फंसाने के लिए कैसे नहीं गिरेंगे। इस बात पर सहमत हुए कि वह, तिवाना, सिद्धू और हरबंस लाल , सीजे, जेजे। अधिकार है और बहुत कम प्रदर्शनकारी हैं और यही पृष्ठभूमि थी, सीजे श्री संधावालिया ने संविधान के अनुच्छेद 229 का दुरुपयोग किया और मैं विरोध करने के लिए बाध्य था और सीजे श्री संधावालिया को टिप्पणी करने के लिए कहा गया था, एक बार नहीं बल्कि दो बार और उन्हें टिप्पणी देने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और इस स्थिति में मेरे प्रति उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं है। फास्टन, आप सभी को, मुझे अवश्य, लेकिन अनुग्रह न खोएं, स्वस्थ मिसालों को न रौंदें, अपने स्वयं के उच्च न्यायालय के रिपोर्ट किए गए फैसले को न रौंदें, यानी, क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1973, पृष्ठ 1106, जिसने साबित किया कि मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किसी भी निम्नतम स्तर को छू सकते हैं और यहां तक कि उप रजिस्ट्रार को गलत निर्देश भी दे सकते हैं।

* * * * *

'ई' आप 1973 में सुनाए गए फैसले से प्रेरणा लेने के लिए तैयार नहीं हैं और यह सब इसलिए है क्योंकि आप सीजे श्री एस. एस. संधवालिया को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते, आप सेवानिवृत्ति के करीब हैं, जबकि उन्हें कई वर्षों तक पद पर बने रहना है, यदि उन पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है उसके दुर्व्यवहार और कदाचार के कारण, और इसलिए, आप अपने बेटों और रिश्तेदारों की ओर देख

रहे हैं, जो आपके कारण पैसा कमा रहे हैं और आप चाहते हैं कि यदि सीजे नाराज़ हो, तो वह आपके रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के पैसे कमाने की राह में बाधा बन जाएगा।

* * * * *

'एफ' चूंकि चिह्नित भाग पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है, न ही पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए, स्पष्टता के लिए, मैं चिह्नित भाग को इस आशा के साथ पुन: प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप या कार्यालय पुष्टि करेगा कि इसके बिना और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड के बिना, जिसे सीजे श्री संधावालिया ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से रोक दिया है।"

हमने सुविधा के लिए 1979 के सीओसीपी नंबर 22 और 23 में कुछ हिस्सों को चिह्नित किया है क्योंकि इन्हें शुरुआत में नोटिस जारी करने वाली बेंच द्वारा चिह्नित नहीं किया गया था।

15. उनके खिलाफ सभी 11 मामलों में 22 अक्टूबर, 1979/7 नवंबर, 1979 का 17 कागजों में उत्तर दिया गया। यह शुरू होता है: -

"आपराधिक मूल संख्या 7 से 11, आपराधिक मूल संख्या 18 और आपराधिक मूल संख्या 19 से 23, सभी 1979 के मामले में और माननीय न्यायमूर्ति एमआर शर्मा और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. एस. सिद्धू के समक्ष निपटान के लिए लंबित हैं।

सुनवाई की अगली तारीख..... 23 अक्टूबर 1979 (स्थगित)
12 नवम्बर 1979 तक)

मामला सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए एक है और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444/78 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें माननीय मुख्य

न्यायाधीश श्री एसएस संधावालिया की भूमिका अत्यधिक निंदनीय है और एक तरफ सबसे अधिक बचाव के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ है। भ्रष्ट, यानी, सर्वश्री बंसी लाल और सुकदेव पार्षद आईएएस और दूसरी ओर याचिकाकर्ता को ब्रिटिश शासन के पुराने तरीके से पीड़ित करने के लिए, जहां। प्रजा के कर्तव्य और सरकार के अधिकार प्रबल हैं, न कि भारत का संविधान, जिसके तहत माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री संधावालिया, श्री न्यायमूर्ति एस. सी. मितल और श्री न्यायमूर्ति के. एस. तिवाना ने शपथ ली।"

इस उत्तर में प्रतिवादी ने उसी प्रकार की असंयमित और तिरस्कारपूर्ण भाषा का उपयोग करते हुए एक ही बात को अलग-अलग स्थानों पर दोहराया, जैसा कि उसने पत्रों/संचारों में इस्तेमाल किया था।

इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को संबोधित, जो उपरोक्त 11 आपराधिक मूल अवमानना मामलों की शुरुआत का आधार थे। उन्होंने इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मौजूदा न्यायाधीशों और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के संबंध में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे उनके द्वारा न्यायिक और कुछ मामलों में प्रशासनिक रूप से लिए गए निर्णयों के प्रति अपनी व्यक्तिगत नापसंदगी प्रदर्शित हुई। हालाँकि यह इन मामलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं था, लेकिन उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल , हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवी लाल और दैनिक ट्रिब्यून के संपादक श्री प्रेम भाटिया का अशोभनीय तरीके से उल्लेख किया। उत्तर में अधिकांश मामला उनके द्वारा दायर 1978 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444 के आसपास केंद्रित है, जिसे इस न्यायालय की पूर्ण पीठ, श्री आरएल लांबा और मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के समक्ष उनकी इच्छा के अनुसार सूचीबद्ध नहीं किया जा सका। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष। उन्होंने कुछ समाचार पत्रों में छपी कुछ

खबरों का भी हवाला दिया, जिनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल की आलोचना की गई थी। उन्होंने इस न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 193 के तहत स्थापित पूर्व विधायक श्री राम लाल के मामले का भी उल्लेख किया, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, करनाल की अदालत में उन्हें बरी कर दिया गया था। उस मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायाधीश और इस न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश जेवी गुप्ता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर के साथ उन्होंने अपने नाम से दिनांक 14 सितंबर, 1979 का एक मुद्रित पत्र संलग्न किया, जिसमें न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेट के बारे में भद्दे हमले और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। प्रतिवादी ने फिर से अपने उत्तर में इस न्यायालय के एक न्यायाधीश के प्रति आक्रामक और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है। हालाँकि हम उत्तर को विस्तार से प्रस्तुत करके निर्णय को लंबा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अंश आवश्यक लगते हैं। पहला उनके उत्तर के पृष्ठ 3 पर है:-

> "याचिकाकर्ता ने हमेशा गलत धारणा बनाई है कि सीजे श्री संधवालिया, जस्टिस एससी मितल और जस्टिस केएस तिवाना के हाथों में न्याय की छड़ी सीधे और न्याय के तराजू के अलावा और कुछ नहीं हो सकती है, जैसा कि अपेक्षित है, संतुलित है, -वीडियो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों/न्यायपालिका के मानक लेकिन सबसे भ्रष्ट के प्रति अधिक और न्याय के प्रति कम स्नेह रखने वाले श्री एसएस संधावालिया की मनमानी भूमिका ने याचिकाकर्ता की धारणा को गायब कर दिया है। और ये उनके अपवित्र मानक थे और ये याचिकाकर्ता के विरोध थे, जिसने याचिकाकर्ता को अपने अधिकार के दुरुपयोग के माध्यम से इन अवमानना नोटिसों की मुसीबत में डाल दिया, फिर भी याचिकाकर्ता इन माननीय न्यायाधीशों से बिल्कुल भी नाखुश नहीं है।
>
> जनता की निगाहों और जनता के भविष्य के मार्गदर्शन के लिए

ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए न्यायिक रिकॉर्ड के सामने रखा जाना चाहिए, न कि उन वर्गों के लिए जिनसे ये अभिजात वर्ग, यानी, न्यायमूर्ति संधवालिया, न्यायमूर्ति एससी मित्तल और न्यायमूर्ति केएस तिवाना आते हैं।"

दूसरा भाग इस भाषा में उनके उत्तर के पृष्ठ 8 पर है: -

"ये माननीय न्यायाधीश, संधावालिया और केएस तिवाना न केवल अधीनस्थ न्यायपालिका की निगरानी करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने स्वयं दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया और याचिकाकर्ता सीजे श्री संधावालिया के आचरण की व्याख्या करने के लिए बाध्य है, जिन्होंने भ्रष्टों को गले लगा लिया है। बंसी लाल , सुखदेव पार्षद। इससे पहले याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करने के लिए बाध्य है कि वह इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि "कठोर शब्दों से हड्डी नहीं टूटती" लेकिन सामान्य ज्ञान की एक और कहावत भी याचिकाकर्ता के नोटिस से बच नहीं सकती है जो है: "पत्थर हिलते नहीं हैं" आँसू" और यह स्वाभाविक है कि याचिकाकर्ता से पूछा जा सकता है कि यह इन माननीय न्यायाधीशों, यानी सर्वश्री संधवालिया, एससी मितल और केएस तिवाना, जेजेजे पर क्यों लागू होता है।"

तीसरा उनके उत्तर के पृष्ठ 10 पर है: -

"आपातकाल के दौरान, कुछ न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर दिया गया था और बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बार एसोसिएशन ने अन्य राज्यों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है और इस तरह की रिपोर्ट प्रेस में दी गई थी लेकिन ट्रिब्यून जब याचिकाकर्ता ने सीजे श्री संधावालिया, जस्टिस एससी मितल, जस्टिस केएस तिवाना और श्री एनएल पूथी,

न्यायिक मजिस्ट्रेट और बंसी लाल , भजन लाल की भूमिका के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की तो श्री प्रेम भाटिया ने खबर प्रकाशित नहीं की। याचिकाकर्ता के बयान और पी-1 से पी-88 तक के प्रदर्शनों का उल्लेख करें, जिसमें एक समाचार पत्र की फोटोस्टेट प्रति भी शामिल है, जिसमें पहले पन्ने पर बंसी लाल, भजन लाल की तस्वीरें एक फुट नोट के साथ प्रकाशित हुई थीं:- बंसी लाल भजन लाल एंड कंपनी:

तस्करों और कमीशन एजेंटों ने न्यायमूर्ति केएस तिवाना की गहरी बुद्धि को आकर्षित नहीं किया है क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना लेंस और विवेक सीजे श्री संधावालिया को दे दिया था, जिन्होंने बंसी लाल और सुखदेव पार्षद दोनों को आगे गिरवी रख दिया था। सुखदेव पार्षद को एक शो रूम करनाल में मिला आरोपी विधायक श्री राम लाल के खिलाफ रास्ता और अधिकार के बिना, जबकि माननीय न्यायाधीश एडी कौशल ने उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में धारा 193 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया, उन्होंने सुखदेव पार्षद और एसके सेठी की तरह, आईपीएस ने पहले से ही फर्जी रिकॉर्ड बनाए थे, उन्हें अदालत में इस्तेमाल किया था कार्यवाही और एक और त्रासदी यह है कि न्यायमूर्ति कौशल का आदेश इस उच्च न्यायालय में लगभग 30 महीनों तक दबा कर रखा गया और सब कुछ रिकॉर्ड में है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि इन सभी भ्रष्टों, झूठे रिकॉर्ड बनाने वालों ने हाथ मिला लिया जैसा कि ऊपर आरोप लगाया गया है और न केवल- सी.आर.एल. याचिकाकर्ता का पुनर्विचार खारिज कर दिया गया लेकिन आरोपी विधायक राम लाल को भी बरी कर दिया गया और इस प्रकार यह भी रिकॉर्ड पर है कि सबसे वरिष्ठ वकील

श्री हीरा लाल सिब्बल, न्यायमूर्ति एडी कौशल से जो काम नहीं करवा सके, वह मिल गया है। भजन लाल , जेवी गुप्ता द्वारा सीजे श्री संधावालिया की सहमति और आशीर्वाद से एक छोटे न्यायिक अधिकारी, श्री बीपी जिंदल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से किया गया, जिन्हें सभी सक्षम लोगों की गंदी भूमिका के कारण दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए किसी पवित्र उद्देश्य के विरुद्ध हाथ मिलाना, इस प्रकार न्याय के स्रोत को प्रदूषित करना।"

न्यायालय की अवमानना के नोटिस के जवाब में प्रतिवादी की मनमौजी प्रवृत्ति को ध्यान में रखने के लिए इन अंशों को पुन: प्रस्तुत किया गया है। उत्तर के अन्य भाग भी हैं जिनमें समान रूप से खराब और अवमाननापूर्ण भाषा का उपयोग किया गया है, यदि बदतर नहीं है। प्रतिवादी ने इस उत्तर में जोर देकर कहा कि पिछला पत्राचार और संचार उसका बचाव है और वह चाहता है कि उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। उत्तर के पृष्ठ 16 पर अंत में उन्होंने लिखा: -

"याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के खिलाफ शासन के निर्वहन के लिए बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि विस्तृत निर्णय के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि जनता, जिनमें से कुछ मूर्ख हैं और अन्य आने वाली पीढ़ियों के साथ मिलकर उनकी भूमिका और आचरण के बारे में समझ सकें इन माननीयों को क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1973 पृष्ठ 1106 में सीजे श्री हरबंस सिंह (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति डीके महाजन (सेवानिवृत्त) के आचरण के बारे में पता चला है।

वह यह भी चाहते थे कि विधायक श्री राम लाल के मामले में मुख्य न्यायाधीश, जेवी गुप्ता, जे. और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल को अवमानना नोटिस जारी किया जाए, हालांकि अदालत की अवमानना (पंजाब और हरियाणा नियम, 1974) के नियम 15(1) के तहत पेपर बुक तैयार की गई है। जिसे इसके बाद इस न्यायालय

द्वारा बनाए गए नियमों के रूप में जाना जाता है, उनमें न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की आपूर्ति की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने उत्तर के अंत में कहा: -

"अवमानना के इन नोटिसों पर निर्णय लेने के लिए बहस के लिए पेपर-बुक की डिलीवरी के बाद कोई भी तारीख तय की जाएगी।

16. हालाँकि प्रतिवादी ने इन सभी मामलों में 22 अक्टूबर, 1979/7 नवंबर, 1979 का एक उत्तर प्रस्तुत किया था, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में बताया गया है, लेकिन 16 सितंबर, 1980 को उसने एक 1979 का एम सीओसीपी 7 और उत्तर दाखिल किया, जिसे एक अनंतिम और अधूरा उत्तर बताया। इसमें उन्होंने लगभग उन्हीं चीजों को दोहराया, जो उनके पत्रों, संचार और पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित संयुक्त उत्तर का विषय-वस्तु हैं, लेकिन बहुत ही निंदनीय और दुर्भावनापूर्ण भाषा में लिखे गए थे।

17. राम पियारा के खिलाफ शुरू किए गए अवमानना के सभी 11 मामलों में समान विशेषताएं हैं, जिनमें एक ही प्रकार के आरोप शामिल हैं और उन्होंने खुद उन सभी में एक समान जवाब दाखिल किया है। हम सभी मामलों को एक सामान्य निर्णय द्वारा तय करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं।

18. हमने पाया कि 5 जुलाई, 1979 को 1979 के सीओसीपी संख्या 19 से 23 में प्रतिवादी को जारी किए गए नोटिस यह बताने के लिए थे कि क्यों न उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। इन नोटिसों के अनुपालन में, राम पियारा प्रतिवादी उपस्थित हुए और इस निर्णय के पैरा 15 में उल्लिखित एक समग्र उत्तर दाखिल किया। वह कार्यवाही में शामिल हुए और इन सभी पत्रों और संचारों के लेखकत्व को स्वीकार किया। 1979 के सीओसी संख्या 7 में मुख्य पेपर

बुक के पृष्ठ 97 पर उनके उत्तर के पैरा 16 में, जिसे हालांकि पहले पुन: प्रस्तुत किया गया था, उचित नोटिस के लिए पुन: प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पैरा में कहा गया है:-

> "याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के खिलाफ शासन के निर्वहन के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, बल्कि विस्तृत निर्णय के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि जनता, जिनमें से कुछ मूर्ख हैं और अन्य, आने वाली पीढ़ियों के साथ मिलकर भूमिका और आचरण के बारे में समझ सकें इन माननीयों में से जैसा कि मुख्य न्यायाधीश श्री हरबंस सिंह (सेवानिवृत्त) और न्यायमूर्ति डीके महाजन (सेवानिवृत्त) के आचरण से क्रिमिनल लॉ जर्नल 1973, पृष्ठ 1106 में ज्ञात हुआ है।

उत्तर के अंत में उन्होंने आगे कहा: -

> 'इन अवमानना नोटिसों पर निर्णय लेने के लिए बहस के लिए पेपर बुक की डिलीवरी के बाद कोई भी तारीख तय की जाएगी।'

5 जुलाई, 1979 को बेंच ने इन सीओसी नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 ऑफ 1979 में कारण बताओ नोटिस भेजा था, लेकिन प्रतिवादी नहीं चाहता था कि उसे बरी किया जाए, जैसा कि स्पष्ट है। अनुच्छेद ऊपर उद्धृत किया गया है, लेकिन इसका निर्णय, इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए आमंत्रित किया और यह मानते हुए कार्यवाही में शामिल हो गए कि उनके खिलाफ नियम जारी किया गया था, जिसे वह बरी नहीं करना चाहते थे। इन मामलों की सुनवाई कर रही विभिन्न पीठें भी उनके जवाब के बाद इसी तरह की धारणा पर आगे बढ़ीं। वह इस तरह के पत्राचार में शामिल होने के अपने अधिकार का दावा करते हुए पूरे मामले का फैसला चाहते थे। यद्यपि प्रतिवादी ने स्वेच्छा से अपने आचरण से

जांच का दायरा बढ़ा दिया है, हम रिकॉर्ड को सीधा करना आवश्यक समझते हैं क्योंकि हमने स्वयं इन पांच मामलों के रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। प्रतिवादी के उत्तर के बाद, इस मामले को पीठों द्वारा नियमित मामले के रूप में माना गया और प्रतिवादी ने स्वयं इसे अवमानना के नोटिस के रूप में लिया था और वह निर्णय चाहता था।

19. श्री राम पियारा 3 प्रतिवादियों ने कहा कि, 18 मई 1979 को उनके द्वारा दायर आपराधिक विविध संख्या 2548 1979, वह चाहते थे। उनके द्वारा उल्लिखित कुछ पत्रों की प्रतियां। इस विविध आवेदन के पृष्ठ 5 पर उन्होंने 18 सितंबर, 1978, 25 अक्टूबर, 1978 और 25/27 दिसंबर, 1978 को उनके द्वारा भेजे गए संचार की आपूर्ति के लिए प्रार्थना की। हमारी पूछताछ पर, कार्यालय ने हमें सूचित किया है कि राम पियारा प्रतिवादी हैं। 25 मई, 1979 को विविध आवेदन संख्या 2548, दिनांक 18 मई, 1979 के संदर्भ में, संचार की प्रतियां प्राप्त करने के लिए, दिनांक 18 सितंबर, 1978, 25 अक्टूबर, 1978, 25/27 दिसंबर, 1978 और 21sf को एक आवेदन दाखिल करें। सितंबर, 1978. यह आवेदन राम पियारा ने किया था, जिसमें सी.आर. 1979 की विविध संख्या 2548 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसे कार्यालय द्वारा 25 मई 1979 के आवेदन संख्या 2753 के रूप में दर्ज किया गया था। पहले तीन संचारों की प्रतियां, अर्थात् 18 सितंबर, 1978, 25 अक्टूबर, 1978 और 25/ 27 दिसंबर, 1978 को इस न्यायालय की प्रतिलिपि एजेंसी द्वारा प्रति वीपीपी उनके अनुरोध के अनुसार उन्हें प्रदान की गई थी। 21 सितंबर, 1978 का चौथा संचार उन्हें भेजा गया था, - संख्या 26190, दिनांक 25 जुलाल , 1979 के माध्यम से। कार्यालय का यह रिकॉर्ड साबित करता है कि प्रतिवादी द्वारा मांगी गई प्रतियाँ, - 1979 की आपराधिक विविध संख्या 2548 के माध्यम से प्रतिलिपि एजेंसी को उसके आवेदन पर, भुगतान पर, उसे आपूर्ति

की गई। 1979 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 2548 पर बेंच द्वारा किसी विशिष्ट आदेश की अनुपस्थिति का यही कारण हो सकता है। रिकॉर्ड पर ध्यान देने के बाद हमने पाया कि प्रतिवादी ने बहस के समय हमारे सामने जो अनुरोध किया था, वह कमजोर था, और पहले भी, निराधार था और कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं कर रहा था। हम पाते हैं कि प्रतिलिपियाँ

नियमों के नियम 15(1) के तहत तैयार की गई पेपर बुक प्रतिवादी को आपूर्ति कर दी गई है।

20. प्रतिवादी द्वारा तीसरी आपत्ति उठाई गई कि इन मामलों में उसे नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह आधार लिया है, - 21 जुलाल 1981 को इस न्यायालय में प्रस्तुत आपराधिक विविध संख्या 3243/1981 के माध्यम से। इसमें आग्रह किया गया आधार यह है कि संचार भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को संबोधित किया गया था, जो प्रशासनिक हैं और उच्च न्यायालय पर संवैधानिक प्राधिकारियों और संचार को उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों को संबोधित किया गया है, जो प्रकाशन के दायरे में नहीं आता है। इन्हें प्रतिवादी ने अपनी दलीलों के दौरान भी दोहराया। हालाँकि 1981 के इस आपराधिक विविध संख्या 3243 में इस तर्क का समर्थन करने के लिए प्रतिवादी द्वारा कानून के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अपने मौखिक संबोधन में, उन्होंने न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 6 पर भरोसा किया, जिसे इसके बाद कहा गया है। कार्यवाही करना। धारा 6 इस प्रकार है:-

> "6. कोई व्यक्ति किसी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के संबंध में सद्भावनापूर्वक दिए गए किसी भी बयान के संबंध में अदालत की अवमानना का दोषी नहीं होगा। .....
>
> (a) किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय, का

(b) उच्च न्यायालय, जिसके वह अधीनस्थ है।

स्पष्टीकरण– इस धारा में, 'अधीनस्थ न्यायालय' का अर्थ उच्च न्यायालय के अधीनस्थ कोई भी न्यायालय है।"

इस प्रावधान का उद्देश्य इसकी भाषा से स्पष्ट है। यह उन न्यायालयों से संबंधित है जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के अधीन नहीं हैं। इस धारा की भाषा से यह संदेह नहीं रह जाता कि इसका संबंध केवल उन न्यायालयों से है, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। धारा 6 के खंड (ए) के तहत जिला और सत्र न्यायाधीश और जिला मजिस्ट्रेट शामिल हैं और इस प्रावधान के खंड (बी) में उच्च न्यायालय का विशेष उल्लेख किया गया है। इसमें उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, जो अभिलेख न्यायालय है और इसकी उत्पत्ति संविधान से हुई है, जहाँ से इसकी शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं। धारा 6 उच्च न्यायालय पर किसी भी एजेंसी या अदालत की पर्यवेक्षी शक्तियों की बात नहीं करती है और उस मामले के लिए प्रतिवादी द्वारा अपने कार्यों के लिए सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है, संचार, 1979 के सीओसीपी नंबर 7 का आधार एकमात्र है राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री को संबोधित प्रतिवादी के पत्रों और संचार का संपूर्ण सेट भारत के मंत्री। इसके आधार पर प्रतिवादी की धारणा कि कोई नोटिस उसे जारी नहीं किया जा सकता है, यह बेहद गलत है।

तर्क का दूसरा पहलू यह है कि इस मामले में किसी भी प्रकाशन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि संचार मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को संबोधित थे, समान रूप से अप्रभावी है। मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबोधित कोई भी संचार फाड़ा या फेंका नहीं जा सकता। इसे उच्च न्यायालय में कार्यरत संबंधित कर्मचारियों को संरक्षित करने और रिकॉर्ड के रूप में रखने के लिए दिया जाना चाहिए। यह प्रतिवादी

का मामला है कि उसने अपने पिछले पत्रों के अनुस्मारक के माध्यम से कुछ वर्तमान संचार भेजे थे। इससे पता चलता है कि वह चाहते थे कि उनके पहले पत्रों को संरक्षित किया जाए या कम से कम उनका विचार था कि उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। वह उनके आधार पर कुछ कार्रवाई चाहता था और कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती थी जब तक कि उन्हें कार्यालय में कामकाजी हाथों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। आवश्यक रूप से ऐसे संचार उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड कार्यालय में जाने चाहिए। भले ही उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी हो, इन्हें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, अधीक्षकों आदि सहित उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को देना होगा और फाइलों में संलग्न करना होगा। यह प्रक्रिया, जिसे छोड़ा या टाला नहीं जा सकता है और इस तथ्य के बावजूद कि सामग्री अपमानजनक, निंदनीय, अपमानजनक आदि है, को अलग-अलग व्यक्तियों के हाथों में जाना पड़ता है, जो न्यायालय को उपहास, बदनामी या किसी भी तरह से लांछित करने के लिए प्रकाशन के पर्याप्त है, जैसा कि कानून का इरादा है।

प्रतिवादी की ये आपत्तियां कि उसे नोटिस जारी नहीं किए जा सकते, इतनी नाजुक हैं कि उसे अवमानना के नोटिस जारी करने की इस अदालत की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता।

21. यह आग्रह किया गया था कि सुनवाई के समय उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं थी और यह अदालत उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी नहीं कर सकती थी, जैसा कि इस अदालत ने 5 मई, 1980 और 26 नवंबर, 1980 को दो बार किया था। ये आदेश नियमों के तहत पारित किए गए थे, जो ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं। प्रतिवादी ने इस न्यायालय के 26 नवंबर, 1980 के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और वहां से उसका दावा खारिज हो गया था।

22. प्रतिवादी की अगली आपत्ति बहस के दौरान और पहले चरण में दायर करके उठाई गई। विविध आवेदन यह है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का कोई आरोप तय नहीं किया गया है या उन्हें बताया नहीं गया है। उन्होंने आग्रह किया है कि जब तक इस तरह का आरोप तय नहीं हो जाता या कहा नहीं जाता, तब तक उन पर अदालत की अवमानना का मामला नहीं चलाया जा सकता. प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर बहस करते हुए। यह स्पष्ट नहीं किया कि जब उन्होंने आग्रह किया कि उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया है या कहा नहीं गया है तो उनका क्या मतलब था। यदि उसके द्वारा बताए गए आरोप तय करने का मतलब दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत आरोप तय करना है, तो वह गलत धारणा के तहत है। यह अधिनियम अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है। अधिनियम अपराध का संज्ञान लेने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित करता है। धारा 14 के तहत यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समक्ष किए गए अपराधों से निपटने और निर्णय लेने के लिए संज्ञान लेने की एक प्रक्रिया प्रदान करता है। यह अपील दायर करने की अपनी प्रक्रिया निर्धारित करता है और अपराध का संज्ञान लेने के लिए अपनी स्वयं की सीमा अवधि निर्धारित करता है। धारा 23 के तहत इसने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को इसकी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होने वाले नियम बनाने की शक्तियां प्रदान की हैं। इस न्यायालय ने स्व-निहित नियम बनाए हैं, जो अधिनियम की धारा 23 के तहत वैधानिक होने के कारण इसका एक हिस्सा हैं। अधिनियम या नियम कहीं भी 'आरोप' शब्द को परिभाषित नहीं करते हैं। अधिनियम के तहत, आरोप नोटिस में कहा गया है या जैसा कि उस सामग्री से बनाया गया है जिसके आधार पर इसे जारी

किया गया है, एक आरोप के रूप में माना जाएगा। आरोप का अभियोग कहा गया है: जैसे ही किसी अवमाननाकर्ता को नोटिस भेजा जाता है। यह एक तरह से धारा 14(1)(ए) से परिलक्षित होता है, जहां सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उनके सामने अपराध करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है और उसे अवमानना के बारे में लिखित रूप से सूचित कर सकता है- जिसके साथ वह आरोपित है। इसे दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय किए गए आरोप के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। नोटिस और प्रत्येक मामले में बेंच द्वारा चिह्नित अलग-अलग हिस्सों के आधार पर लगाए गए आरोप इन मामलों में प्रतिवादी द्वारा अच्छी तरह से समझे जाते हैं और यह उनके द्वारा दाखिल किए गए जवाब और उनके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विविध आवेदनों से भी स्पष्ट है। इन कार्यवाहियों के दौरान उच्च न्यायालय को भेजा गया या भेजा गया। ये मुख्य मामले के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, यानी 1979 के सीओसी नंबर 7 और यहां तक कि प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में भी इन पर भरोसा किया जाता है। नोटिस में आरोप का उल्लेख किया गया है, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से समझा है और उसी दृढ़ता के साथ इसका विरोध किया है, जैसा कि उन्होंने किया था। पत्र और संचार लिखा। अवमानना के आरोप को समझते हुए, प्रतिवादी ने अपने उत्तर, दिनांक 22 अक्टूबर, 1979 और 7 नवंबर, 1979 में कहा: -

> "याचिकाकर्ता आगे प्रार्थना करता है कि सभी याचिकाएं/संचार, आवेदन, अपील की अनुमति के लिए याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका उपर्युक्त माननीय न्यायाधीशों, याचिकाकर्ता को अवमानना नोटिस संख्या 25 में दायर रिटर्न और याचिकाकर्ता की शिकायतों के संबंध में सितंबर, 1978 से आज तक का संपूर्ण रिकॉर्ड, साथ ही आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444

का अनुसरण /78, आदि, क्योंकि ये सभी दस्तावेज़ याचिकाकर्ता का बचाव हैं।"

इन अवमानना नोटिसों में कुछ भी अस्पष्ट नहीं है और अब अवमाननाकर्ता यह कहने के लिए पलट नहीं सकता है कि आरोप नहीं बताया गया था या पूर्वाग्रह का तर्क खड़ा करने के लिए उसे अनुचित तरीके से बताया गया था क्योंकि वह अपने खिलाफ मामले को अच्छी तरह से समझ चुका था। वह अपने बचाव में अपने स्वयं के संचार पर निर्भर रहे हैं और दो दिनों तक इस न्यायालय के समक्ष मामले पर बहस की है।

23. आइए जानते हैं उनके मुख्य बिंदुओं पर, क्या? श्रीराममिरपी कॉमरेड ने पत्रों/संचारों के माध्यम से, इन मामलों के विषय, फैसले के पहले भाग में निकाले गए अंशों को लिखकर, अदालत की आपराधिक अवमानना का अपराध किया है जैसा कि अनुभाग में निहित है अधिनियम की धारा 2(सी) संदर्भ के लिए धारा 2{सी) को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।-

(a) ... »

(b) ..

(c) 'आपराधिक अवमानना' का अर्थ है किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना जो कि- '

(i) किसी भी न्यायालय को लांछित करता है या लांछित करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसके अधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(ii) किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह,

या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(iii) किसी अन्य तरीके से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है;

यह प्रावधान *बरदाकांत मिश्रा* बनाम *उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और अन्य*[2], के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था, जहां इन प्रावधानों के संबंध में उस मामले में यह देखा गया था: -

"34 यह देखा जाएगा कि परिभाषा में प्रयुक्त शब्दावली अवमानना के अंग्रेजी कानून से उधार ली गई है और उन अवधारणाओं का प्रतीक है जो उस कानून से परिचित हैं जो कि बड़े पैमाने पर भारत में लागू किया गया था। '(बदनामी करना)', 'अदालत के अधिकार को कम करना', 'हस्तक्षेप', 'रुकावट' और न्याय प्रशासन' ये सभी अभिव्यक्तियाँ हमारे उपमहाद्वीप की कानूनी मुद्रा में चली गई हैं और इन्हें इस अर्थ में समझा जाना चाहिए जहां आवश्यक होने पर उन्हें अंग्रेजी कानून की सहायता से अब तक हमारी अदालतों द्वारा समझा गया है।

35. पहला उप-खंड आम तौर पर उस चीज़ से संबंधित है जिसे अदालत के घोटाले के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा हल्सबरी तीसरे संस्करण में खंड 8, पृष्ठ 7 पैरा 9 में की गई है:

'न्यायाधीशों पर निंदनीय हमलों को इस सिद्धांत पर कुर्की या प्रतिबद्धता द्वारा दंडित किया जाता है कि वे जनता के खिलाफ हैं, न कि न्यायाधीश सार्वजनिक न्याय में बाधा डालते हैं; और एक न्यायाधीश पर

[2] ए आई आर 1974 एस सी 720।

मानहानि, ताकि यह न्यायालय की अवमानना का मामला बनता है, अवश्य हुआ होगा ऐसी बाधा पैदा करने के लिए गणना की गई सज़ा पूरी अदालत या भारत की रक्षा के उद्देश्य से नहीं दी गई है, अदालत के दृश्य न्यायाधीशों को हमले की पुनरावृत्ति से, लेकिन जनता की रक्षा करने की, और विशेष रूप से उन लोगों की, जो या तो स्वेच्छा से या मजबूरी से अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, 'ट्रिब्यूनल के अधिकार के तहत वे जो शरारत करेंगे। कमज़ोर या कमज़ोर किया गया है।'

उप-खंड (1) उपरोक्त अवधारणा का प्रतीक है और उन मामलों में लागू होता है जब प्रकाशन या अधिनियम द्वारा न्याय प्रशासन का उपहास और अवमानना की जाती है। इसे सार्वजनिक न्याय में 'बाधा' माना जाता है जिससे अदालत के अधिकार को कमज़ोर किया जाता है। उप-खंड (i) अवमानना की एक प्रजाति को संदर्भित करता है जो 'बाधा' एक महत्वपूर्ण तत्व है। उपखंड (ii) न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप की बात करता है और इसकी आम स्वीकृति में न्याय प्रशासन से सीधे जुड़ा हुआ है।

36. जबकि खंड (i) और (ii) उसमें वर्णित विशेष तरीके से क्रमशः रुकावट और हस्तक्षेप से निपटते हैं, खंड (iii) एक अवशिष्ट प्रावधान है जिसके द्वारा न्याय प्रशासन में किसी अन्य प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप को आपराधिक अवमानना माना जाता है।

37. दूसरे शब्दों में, ऊपर उल्लिखित सभी तीन उप-खंड न्याय प्रशासन में बाधा या हस्तक्षेप के संदर्भ में अवमानना को परिभाषित करते हैं। मोटे तौर पर हमारा क़ानून प्रिवी काउंसिल और अन्य अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई बात को स्वीकार करता है कि अवमानना की कार्यवाही हमेशा न्याय प्रशासन के संदर्भ में होती है।

24. प्रतिवादी पर मुख्य रूप से तीन तरीकों से इस न्यायालय को बदनाम करने का आरोप है: (1) निंदात्मक आलोचना करके प्रशासनिक पक्ष में इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एसएस संधावालिया, जो कि उनके द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444/1978 की सुनवाई के लिए एक पूर्ण पीठ गठित करने की उनकी मांग के आगे नहीं झुक रहे हैं, जो कि अपमानजनक संचार के दबाव में है। इसमें एससी मितल, जे. और प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करने वाले इस न्यायालय के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आलोचना भी शामिल है: (2) कि प्रतिवादी द्वारा एसएस संधवालिया, सीजे की ओर इस्तेमाल की गई भाषा, उम्र के लिए पूरी तरह से प्रशासनिक पक्ष पर उनकी आलोचना करती है। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का निंदनीय प्रभाव पड़ता है; और (3) न्यायाधीश के रूप में उनके आचरण और आदेश पारित करने और निर्णय देने में उनके न्यायिक कार्यों के निर्वहन में इस न्यायालय के न्यायाधीशों की आलोचना करने में उनके द्वारा की गई अदालत की अवमानना।

25. प्रतिवादी के इस तर्क के आलोक में कि उसने पहले और दूसरे बिंदु पर कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसने प्रशासनिक पक्ष में इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एससी मितल, जे और हरबंस सिंह, सीजे (सेवानिवृत्त) की आलोचना की है। यह तुरंत नोटिस आकर्षित करता है कि न्याय प्रशासन का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब केवल न्यायिक पक्ष में अदालतों के समक्ष लंबित मामलों का न्यायनिर्णयन है या इसमें प्रशासनिक कार्य भी शामिल हैं मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के, जो न्यायाधीश के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के आवश्यक गुण हैं। यह मामला बरदाकांत मिश्रा के मामले (सुप्रा) में सीधे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया, जहां उनके आधिपत्य ने पैरा 43 में कहा: -

“हमें 'न्याय प्रशासन' अभिव्यक्ति की किसी व्यापक परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से और लोगों के मन में, न्याय प्रशासन विशेष रूप से संवैधानिक रूप से स्थापित न्याय न्यायालयों से जुड़ा हुआ है। ऐसे न्यायालयों की स्थापना भूमि के माध्यम से अनेक क़ानूनों द्वारा की गई है। किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश अपने आप में न्यायालय का प्रतीक होता है, और जब न्याय प्रशासित करने के कार्य में लगाया जाता है तो उसे क्लर्कों और मंत्रिस्तरीय अधिकारियों के पूरक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनका कर्तव्य रिकॉर्ड की रक्षा करना और बनाए रखना, रिट तैयार करना, प्रक्रियाओं की सेवा करना है। आदि। जिन कार्यों में वे लगे हुए हैं वे "पीठासीन न्यायाधीश द्वारा न्याय प्रशासन" की सहायता में कार्य हैं। क्लर्कों और मंत्रिस्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की शक्ति में पीठासीन न्यायाधीश द्वारा उन पर प्रशासनिक नियंत्रण शामिल होता है और यद्यपि इस तरह के नियंत्रण को न्याय की सीट पर बैठे न्यायाधीश के कर्तव्यों से अलग करने के लिए प्रशासनिक के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन इस तरह के नियंत्रण का प्रयोग न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। न्यायिक प्रशासन के दौरान एक न्यायाधीश। न्यायिक प्रशासन न्यायाधीश का एक एकीकृत कार्य है और जहां तक न्यायिक प्रशासन में शुचिता के उच्च मानकों को बनाए रखने का सवाल है, इसमें कोई विच्छेदन नहीं हो सकता है। न्यायालय की पूरी व्यवस्था न्याय प्रशासन के उद्देश्य से होती है और न्यायाधीश अपने सहायकों पर जो नियंत्रण रखता है उसका उद्देश्य न्याय प्रशासन की शुद्धता बनाए रखना भी होता है। ये टिप्पणियाँ देश में न्याय के लिए सभी अदालतों पर लागू होती हैं, चाहे उन्हें न्याय की श्रेष्ठ या निम्न अदालतें माना जाता हो।

पैरा 45 में यह भी कहा गया: -

"केवल पार्टियों के बीच न्यायनिर्णयन का कार्य किसी भी अदालत के लिए न्याय प्रशासन का संपूर्ण कार्य नहीं है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुशासनात्मक नियंत्रण अदालत में निहित है, न कि एक निजी व्यक्ति के रूप में न्यायाधीश के पास। इसलिए, नियंत्रण न्याय के उचित प्रशासन के लिए उतना ही अनुकूल कार्य है जितना कि कानून बनाना या पक्षों के बीच न्याय करना।

सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने पैरा 46 में इसी मामले में आगे कहा: -

"यह स्पष्ट है कि न्याय प्रशासन के लिए क्लर्कों और मंत्रिस्तरीय अधिकारियों को नियुक्त करने का मुख्य न्यायाधीश का यह अधिकार न्याय प्रशासन के हित में उन्हें नियंत्रित करने के अधिकार का तात्पर्य है। यह नियंत्रण कार्य जिसे आमतौर पर एक प्रशासनिक कार्य के रूप में वर्णित किया जाता है, न्याय के प्रशासन को सुरक्षित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, जब मुख्य न्यायाधीश मंत्रिस्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है और उन पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है, तो यह एक ऐसा कार्य है जिसे प्रशासनिक के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन यह वास्तव में न्याय प्रशासन के अंतर्गत है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 की धारा 9 उच्च न्यायालय को कई प्रकार के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ प्रदान करते हुए कहती है कि ऐसे सभी क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ "उस प्रेसीडेंसी में न्याय प्रशासन के लिए और उसके संबंध में हैं जिसके लिए यह स्थापित किया गया है' . भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 106 इसी तरह दर्शाती है कि उच्च न्यायालय के कई क्षेत्राधिकार और उनकी सभी शक्तियाँ और अधिकार 'न्याय प्रशासन के संबंध में हैं, जिसमें न्यायालय के क्लर्कों और अन्य मंत्रिस्तरीय अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति भी शामिल है।' भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 223 मौजूदा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और

अदालत में न्याय प्रशासन के संबंध में उनके न्यायाधीशों की संबंधित शक्तियों को संरक्षित करती है। उस अधिनियम की धारा 224 में घोषणा की गई है कि उच्च न्यायालय को फिलहाल अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन भारत की सभी अदालतों पर अधीक्षण अधिकार होगा और यह अधीक्षण, अब तय हो गया है, अधीनस्थ न्यायालयों के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों दोनों तक विस्तारित है। जब हम अपने संविधान पर आते हैं तो हम पाते हैं कि अनुच्छेद 225 और 227 न्याय प्रशासन के संबंध में इन शक्तियों को संरक्षित करते हैं और कुछ हद तक विस्तारित करते हैं।

पैरा 47 में आयोजित एक ही मामले में उच्च न्यायालय के कार्यों के बारे में निष्कर्ष निकालना: -

"इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी राज्य में सर्वोच्च से निम्नतम तक न्याय की अदालतें अपने संविधान के अनुसार सीधे तौर पर जुड़े कार्यों से जुड़ी होती हैं, न्याय प्रशासन, और यह उन सभी लोगों की अपेक्षा और विश्वास है जिनका इसमें व्यवसाय है या होने की संभावना है कि अदालतें पक्षपात, स्नेह या द्वेष के डर के बिना उच्च स्तर की ईमानदारी से अपने सभी कार्य करती हैं।

26. यह तर्क दिया गया था, जैसा कि श्री राम पियारा प्रतिवादी द्वारा पिछले पैराग्राफ में देखा गया था कि उन्होंने प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय की आलोचना की थी और यह अधिनियम की धारा 2 (सी) में परिभाषित 'आपराधिक अवमानना' की श्रेणी में नहीं आता है। *बरदाकांत मिश्रा के मामले (सुप्रा)* में अपीलकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी तरह का तर्क उठाया गया था कि उच्च न्यायालय के प्रशासन की निंदात्मक शब्दों में भी आलोचना करना अदालत की अवमानना नहीं है। उस मामले में उनके आधिपत्य द्वारा उस तर्क को इन टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया था: -

"इस प्रस्ताव के लिए उच्च अधिकार है कि विशुद्ध रूप से प्रशासनिक

या गैर-न्यायिक मामलों में भी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले न्यायाधीश की निंदात्मक आलोचना आपराधिक अवमानना के बराबर है।"

इसलिए, प्रतिवादी द्वारा यह नहीं कहा जा सका जैसा कि उसने बहस के दौरान कहा था, कि उसकी आलोचना ऐसी भाषा में भी हो जो असंयमित हो, 'आपराधिक अवमानना' के दायरे में नहीं आ सकती।

27. बेंचों के गठन के मामले में, मुख्य न्यायाधीश न्याय प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें शक्तियां प्रदान करने में कानून द्वारा उन्हें दिए गए अपने अधिकार का निर्वहन करता है। मामले का तथ्य यह है कि प्रतिवादी मुख्य न्यायाधीश को प्रभावित करना चाहता था कि उसकी आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444/1978 की सुनवाई पूर्ण पीठ द्वारा की जाए। जब उन्हें अपने अनुचित प्रस्ताव पर उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के विवेक को प्रभावित करने के लिए अपमानजनक और असंयमित भाषा का सहारा लिया, जो पूरा नहीं हो रहा था। इसके बाद प्रतिवादी और अधिक आक्रामक हो गया और उसने मुख्य न्यायाधीश पर पूर्वाग्रह के आरोप लगाने वाले उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। एक उदाहरण का हवाला देते हुए जब मुख्य न्यायाधीश एसएस संधवालिया ने एक न्यायाधीश के रूप में 1978 के आपराधिक संशोधन संख्या 444 पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने अपने मुख्य न्यायाधीश बनने पर निंदनीय हमला किया, इस आशा के साथ कि वह (मुख्य न्यायाधीश) अंततः झुक जाएंगे। उसकी मांग. इस पद्धति से प्रतिवादी चाहता था कि मुख्य न्यायाधीश पीठ के गठन के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, इस तथ्य के बावजूद कि उसकी मांग में योग्यता थी या नहीं, उसके आपराधिक पुनरीक्षण को पूर्ण पीठ के पास भेजने की प्रतिवादी की मांग के पक्ष में।

28. मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के विशाल प्रतिष्ठान का प्रशासन एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के

रूप में अपनी स्थिति के आधार पर चलाता है। वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 225/229 के तहत इन कार्यों का निर्वहन करता है; उच्च न्यायालय प्रतिष्ठान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष तक बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग उनके द्वारा किया गया था। हम इस तर्क के गुण-दोष पर नहीं जाते हैं कि क्या एसएस संधवालिया, सीजे, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष तक बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से सक्षम थे, क्योंकि इसके गुण इन मामलों के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश का वह कार्य उचित है या नहीं, लेकिन तथ्य यह है कि जब तक वह आदेश अस्तित्व में है, किसी को भी मुख्य न्यायाधीश द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन की बदनामी के लिए उद्देश्यों या पूर्वाग्रहों को जिम्मेदार ठहराते हुए अनुचित और अनुचित आलोचना करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति, न्याय प्रशासन में वह कौन सा कर्तव्य निभाते हैं, बरदाकांत मिश्रा के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ मामले के इस पहलू से पूरी तरह आकर्षित हैं।

29. आरोप के तीसरे पहलू के बारे में, इसमें शायद ही कोई संदेह है कि यदि किसी न्यायाधीश की न्यायिक कार्यों के प्रभार में उसकी ईमानदारी के बारे में भूमिका के संबंध में किसी भी अपमानजनक टिप्पणी का उद्देश्य किसी अदालत को बदनाम करना या उसके अधिकार को कम करना है, तो यह यह आपराधिक अवमानना के समान है। जब इस तरह का कोई भी हमला या आलोचना न्याय के प्रशासन में पूर्वाग्रह पैदा करती है, हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप करती है या बाधा डालती है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखती है तो यह भी आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है।

अधिनियम में प्रयुक्त 'स्कैंडलाइज़' शब्द का कोई विशेष या तकनीकी अर्थ नहीं है। इसके सामान्य अर्थ, जो आमतौर पर समझे जाते हैं, को अधिनियम की धारा 2(सी)(आई) के संदर्भ में ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम इसका एक कारण यह भी देखते हैं कि अदालत की बदनामी करने वाला कोई व्यक्ति यह दलील दे सकता है कि वह शब्द के केवल सामान्य शब्दकोश अर्थ समझता था

और क़ानून द्वारा किसी विशेष संदर्भ में दिए गए तकनीकी अर्थों से परिचित नहीं था। हमें यह देखना होगा कि क्या राम पियारा, प्रतिवादी का कृत्य उस शब्द के अर्थ में न्यायालय को बदनाम करने के दायरे में आता है, जिसे आमतौर पर समझा जाता है, और यह भी कि क्या यह धारा 2 (सी) के दायरे में आता है। हमें यह भी देखना होगा कि आचरण क्या है प्रतिवादी ने लिखित रूप से कहा कि संचार न्यायिक कार्यवाही या न्याय प्रशासन में पूर्वाग्रह, हस्तक्षेप और बाधा उत्पन्न करता है या इन चीजों की ओर जाता है।

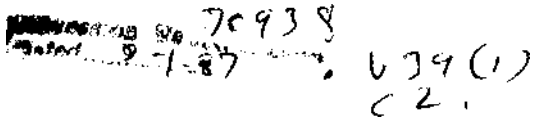

30.शॉर्टर ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, वॉल्यूम II, 1959 संस्करण में दिए गए 'स्कैंडलाइज' शब्द का अर्थ इस प्रकार है: "(किसी व्यक्ति के) आचरण की झूठी या दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट करना;" बदनामी करना; घोटाले की बात करना; शर्म या बदनामी लाना; अपमानित करने के लिए" वेबस्टर्स थर्ड न्यू इंटरनल डिक्शनरी, वॉल्यूम III में, 'स्कैंडलाइज' शब्द के दिए गए अर्थ इस प्रकार हैं: "झूठा या दुर्भावनापूर्ण ढंग से बोलना; बदनामी; बदनाम करना; »निंदा में लाना; अपमान; अपमान; अनैतिक, आपराधिक या अनुचित माने जाने वाले किसी कार्य से भावनाओं, विवेक या औचित्य को ठेस पहुँचाना।

31. अपने तर्कों के दौरान, राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने यह सारी सामग्री न्याय प्रशासन की शुद्धता बनाए रखने और उसकी दक्षता में सुधार करने के विचार से लिखी थी और ऐसा करना उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के रूप में वर्णित किया और इस न्यायालय को भेजे गए संचार और विविध आवेदनों में खुद को इसी रूप में संदर्भित किया। प्रतिवादी ने जो स्वयंभू भूमिका अपनाई है, उसकी इतिहास की पृष्ठभूमि और मुकदमेबाजी में उसकी रुचि के बारे में विस्तार से जांच की जानी है, जिसे वह अपने आपराधिक पुनरीक्षण को सूचीबद्ध करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त

करने के लिए अपना रहा है। जिस तरह से उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ निंदात्मक भाषा के इस्तेमाल के बारे में सोचा। वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा करते हैं और दलीलों में कहा कि अगर न्यायिक प्रशासन में शुचिता बनाए रखने और इस शाखा में दक्षता लाने के अपने उद्देश्य की तलाश में उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो असंयमित भी हो सकती है, तो यह भाषा हो सकती है। इसे नज़रअंदाज़ किया जाए क्योंकि यह नेक इरादे से किया गया था। हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन असीमित सीमा तक नहीं। लोगों को न्याय प्रशासन में उनकी भूमिका में न्यायाधीशों की आलोचना करने का सुरक्षित अधिकार है, लेकिन यह रचनात्मक होना चाहिए। आलोचना बेलगाम और अनियंत्रित नहीं हो सकती. न्यायाधीशों की आलोचना में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता शालीनता की सीमा के भीतर होनी चाहिए। इन सीमाओं को पार नहीं किया जाना चाहिए और यदि कोई न्यायाधीश द्वारा सदियों से पारित और विभिन्न देशों की सर्वोच्च अदालतों द्वारा समय-समय पर सुधार किए गए कानून द्वारा निर्धारित ऐसी सीमाओं का उल्लंघन या उल्लंघन करता है, तो अदालतों को आगे आना होगा। यह जाँचें। अवमानना कानून की सामान्य नीति यह है कि अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की दिशा में अनिच्छा से कदम बढ़ाया जाना चाहिए।

इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग आरक्षण के साथ किया जाना चाहिए। कभी-कभी अभद्रता या अनुचितता के थोड़े स्वर वाली टिप्पणियों को न्यायाधीशों द्वारा व्यक्तिगत अपमान नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें इस पर ध्यान देना होगा जब न्याय के प्रशासन के संबंध में उनकी न्यायिक क्षमता में न्यायाधीशों के बारे में की गई टिप्पणियाँ ऐसी हों जो अदालतों को बदनाम करने या पक्षपात करने या न्याय प्रशासन या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए की जाती हैं- न्यायाधीशों द्वारा, जो अपने पद के कारण स्वभाव से ही कठोर होते हैं और संयम तथा सत्यनिष्ठा के मामले में अनुभवी होते हैं, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता या उनका समर्थन नहीं किया जा सकता। न्यायाधीशों की गरिमा की अतिरंजित धारणा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। इसका सहारा तभी लिया जाना चाहिए जब उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीशों के अधिकार पर ज़बरदस्त हमला किया जाए ताकि न्याय प्रशासन में जिम्मेदारी रखने वाली इस संस्था के अधिकार को कमजोर किया जा सके। इसे बदनाम करना या इसके अधिकार को कम करना; किसी न्यायाधीश के विरुद्ध अपशब्दों और आक्षेपों से युक्त निंदनीय और अपमानजनक भाषा को सुनना कभी भी सुखद नहीं होता है। ऐसे मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों को, जो मानव हैं, उन्हें निंदा करने वाले के सामने शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखना होता है, जो बहस के दौरान कई बार अपने द्वारा लिखे या छपे मामले की तुलना में अधिक जोश और व्यंग्य के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अपने आप पर या जिस संस्था से आप जुड़े हैं उसके बारे में मानहानि का पाठ पढ़ने और उसे अदालत में न्यायाधीश के सामने बार-बार सुनने में हमेशा एक अंतर होता है। इस स्थिति में, जो किसी अन्य व्यक्ति को, जिसका अनुभव न हो, उकसा सकता है; न्यायिक प्रशिक्षण में न्यायाधीश को शांत, संतुलित एवं शीतल रहना होता है। कानून के ये सभी पोषित सिद्धांत हमारे दिमाग में मौजूद थे जब हमने दो दिनों में राम पियारा प्रतिवादी को इस न्यायालय के न्यायाधीशों और कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और पारित न्यायिक आदेशों के खिलाफ जंगली, कटु, अप्रिय और अपमानजनक भाषा में अपने दावे दोहराते

हुए सुना। उनके द्वारा बहस के दौरान अधिकांश समय वह इस न्यायालय का उपहास करते रहे। हम राम पियारा प्रतिवादी के प्रति असहिष्णु नहीं होंगे यदि हम कहते हैं कि इन मामलों में अपनी कार्रवाई के लिए खुद का बचाव करने के लिए उचित अवसर के नाम पर हमने उसे दो दिनों तक पीड़ित किया। हम प्रतिवादी के पिछले आचरण के बारे में कुछ कारकों पर ध्यान देना उचित समझते हैं, जो स्थापित हैं।

वर्ष 1971 में उन्हें अवमानना आपराधिक मूल संख्या 257 और 259/1971 के लिए दो नोटिस जारी किए गए, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया। उनकी अवमाननापूर्ण भाषा और भाषा के गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल के बारे में बेंच की टिप्पणियों को फैसले के पैरा 1 में दोहराया गया है। दूसरी जगह भी वैसा ही बेंच ने उनके बारे में कहा: -

> "विभिन्न पत्रों के उद्धरणों को गुणा करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह बताने के लिए पर्याप्त है कि इन सभी पत्रों की प्रवृत्ति कमोबेश एक ही प्रभाव वाली है, सिवाय इसके कि उत्तरदाता बाद के पत्रों में कुछ समय के लिए अधिक असंयमित भाषा का उपयोग कर रहा था। उच्च न्यायालय श्री लांबा की मदद करने के लिए उनकी शिकायतों को दबा रहा था।'

जैसा कि उनके पत्रों/संचारों से स्पष्ट है, उनका अन्य व्यक्तियों के साथ मुकदमा चल रहा है। 1973 क्रिमिनल एलजे 1106 (सुप्रा) में बेंच की टिप्पणियां ऊपर प्रस्तुत की गई हैं और इस फैसले का पैरा 1 हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो हम मानते हैं कि प्रतिवादी को अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने की आदत है। एचआर सोढ़ी, जे. की टिप्पणियाँ, जिन्होंने 1971 की आपराधिक मूल संख्या 257 और 259 में अदालत के लिए बात की थी, उनका आकलन करने में बहुत सही थीं और जब हमने वर्ष 1981 में मामले की जांच की तो वे सच निकलीं। प्रतिवादी ने सोचा कि इस न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हरबंस सिंह ने उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं किया और वे उनके खिलाफ लिखते रहे, चाहे

उनके प्रति उनका संदर्भ उचित था या नहीं। प्रतिवादी ने सोचा कि एससी मितल, जे. ने किसी प्रशासनिक मामले में श्री आरएल लांबा के पक्ष में कुछ आदेश पारित किए हैं और उन्होंने इस विद्वान न्यायाधीश के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, बिना यह जाने कि इसके लिए कोई अवसर था या नहीं। इन मूल अवमानना मामलों के पत्रों में एससी मित्तल, जे. का उनका संदर्भ, जिस पर हम उचित चरण में चर्चा करेंगे, इसे सहन करेंगे। जब एसएस संधावलिया, सीजे, अपने आपराधिक पुनरीक्षण में पूर्ण पीठ गठित करने के उनके अनुरोध पर सहमत नहीं हुए, तो प्रतिवादी ने स्थिति को स्वीकार नहीं किया और उनके अधिकार का उपहास करना शुरू कर दिया और अवमाननापूर्ण और अपमानजनक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विभिन्न पीठों द्वारा चिह्नित अंशों को फैसले के पहले भाग में पुन: प्रस्तुत किया गया है, जो प्रतिवादी की अदालत के सेवानिवृत्त, वर्तमान न्यायाधीशों, राजनेताओं या यहां तक कि ट्रिब्यून के संपादक सहित किसी को भी नहीं बख्शने की मानसिकता को दर्शाता है। इन पत्रों का चलन दर्शाता है. प्रतिवादी का मन किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति द्वेष से ग्रस्त है जो उस तरीके से काम नहीं करता जैसा वह उससे कराना चाहता है, भले ही दूसरा व्यक्ति किसी भी पद पर हो। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि 1971 के पहले आपराधिक मूल संख्या 257 और 259 में नोटिस जारी होने से उनका साहस बढ़ गया था और उनके मन में यह भावना घर कर गई थी कि वह किसी के भी खिलाफ किसी भी भाषा में बेधड़क कुछ भी कह सकते हैं। बहस के दौरान उन्होंने श्रेय लेने की कोशिश की उनके आचरण और रवैये के लिए, जिसे उन्होंने यह कहते हुए साहसिक बताया कि दो मौकों पर उन्हें इस अदालत में मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों के सामने की गई अदालत की अवमानना के लिए नोटिस जारी किए गए थे। सत्यापन पर हमने पाया कि एमआर शर्मा और एसएस सिद्धू, जेजे द्वारा 1979 की आपराधिक मूल संख्या 25 में प्रतिवादी श्री राम पियारा को अवमानना का एक नोटिस जारी किया गया था और उसी दिन फैसला किया गया था। जिस अधिनियम में नोटिस जारी किया गया था वह इन मामलों में सुनवाई के दौरान प्रतिबद्ध था। एमआर शर्मा और एसएस

सिद्धू, जेजे, राम पियारा के समक्ष पेश होते हुए, प्रतिवादी ने कहा: - "मैं चाहता हूं कि यह न्यायालय स्वतंत्र हो"। उन्हें वहीं नोटिस जारी किया गया और उनके जवाब को बेंच ने इस प्रकार नोट किया: "प्रतिवादी द्वारा कहे गए वे शब्द लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव पर आधारित शुद्ध नैतिक कारणों के लिए केवल अपमानजनक आदेश थे, जिसमें प्रतिवादी ने कुछ कड़वे अनुभवों का स्वाद चखा था।" कुछ माननीय न्यायाधीशों के अयोग्य कार्य"। यह देखते हुए, "ऐसा प्रतीत होता है कि अवमाननाकर्ता ने अपने अनोखे अंदाज में यह भावना व्यक्त करने की कोशिश की है कि उपरोक्त शब्द उसके होठों से छूट गए थे और उसका इस न्यायालय का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था" नोटिस खारिज कर दिया गया।

जो दूसरा नोटिस जारी किया गया था, वह 1979 के आपराधिक मूल संख्या 7 के रिकॉर्ड के साथ संलग्न है। 18 दिसंबर, 1979 को फिर से उसी पीठ के समक्ष उपस्थित होकर, राम पियारा प्रतिवादी ने इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेशों को दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण बताया। बेईमान. उन्हें नोटिस दिया गया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह उचित था। उन्हें अदालत की अवमानना का अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया और अदालत के दोपहर के भोजन के लिए उठने तक कारावास की सजा सुनाई गई। उन पर 1 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया या जुर्माना न भरने पर 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ी। बेंच ने कहा कि: "राम* पियारा की अवमानना करने वाले के आचरण से पता चलता है कि वह अपनी कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बनाने का इरादा रखता है।"

ये उदाहरण जो उन्होंने स्वयं न्यायालय के ध्यान में लाकर उनकी बहादुरी की भावना को उजागर किया, वे न्यायालय के न्यायाधीशों को भयभीत करने के विचार से जानबूझकर अपमानजनक भाषा का उपयोग करने की उनकी जिद और दृढ़ता को दर्शाते हैं ताकि वे या तो उनकी बात सुनने से बच सकें। मामलों या उसकी कड़वी जुबान से डरो। इससे भी अधिक उत्साहित होकर, हालांकि इसके लिए कोई अवसर नहीं था, उन्होंने 3 अगस्त, 1981 को हमारे सामने

प्रस्तुत एक आपराधिक विविध याचिका में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी बख्श दिया, जिनकी पीठ से उनके मामले खारिज कर दिए गए थे।

32. उपरोक्त तथ्यों का एक सारांश, जो क्षेत्र के रिकॉर्ड से प्राप्त किया गया है, यह स्पष्ट है कि यह कोई छिटपुट घटना नहीं है, बल्कि एक वादी योजना है, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा की आड़ में इस न्यायालय के उन न्यायाधीशों के खिलाफ निंदा अभियान शुरू कर दिया है, जिनसे वह अपने पक्ष में फैसला सुनाता है या जिन्होंने उसके खिलाफ मामलों का फैसला किया है। वह कमोबेश अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ नियमित शिकायतकर्ता हैं। उन्होंने श्री आरएल लांबा के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जैसा कि 1971 के आपराधिक मूल संख्या 257 और 259 में दर्ज मामले से स्पष्ट है। उन्होंने शिकायती तरीके से श्री प्रुथी, न्यायिक मजिस्ट्रेट और एक अन्य न्यायिक अधिकारी के आचरण की भी प्रतिकूल आलोचना की थी। जिन्होंने पूर्व विधायक राम लाल के मामले का फैसला किया था, जिसे अक्सर उनके द्वारा विविध अनुप्रयोगों और एक मुद्रित पत्र में संदर्भित किया गया है, जो इन मामलों के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। उनका आचरण एक तरह से अमरीक सिंह के समान है, जिनके मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था और यह अमरीक सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन राज्य के मामले में रिपोर्ट किया गया है। उस निर्णय के उद्धरण से इन दोनों व्यक्तियों की शिकायतों के संबंध में उनके दिमाग की योग्यता के बारे में समानता सामने आएगी। पुनरुत्पादन है: –

> "इस न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए आरोप निंदनीय आरोप हैं।" याचिकाकर्ता असभ्य रहा है। हमने उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने या उनसे अलग होने और इस न्यायालय में माफी मांगने के लिए बार-बार अवसर दिए हैं, लेकिन उसने उन अवसरों का लाभ नहीं उठाया है। इस मामले के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि उसे न्यायालयों के न्यायाधीशों, मजिस्ट्रेटों, एपीडी अधिकारियों को डराने-धमकाने का काम दिया गया है। उन्होंने इस अदालत में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने

विद्वान सरकारी वकील पर धोखाधड़ी और छल का सहारा लेने का आरोप लगाया है।"

इस न्यायालय में विभिन्न पीठों के समक्ष मामलों के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी आवेदन प्रस्तुत करते रहे, जो स्वयं न्यायालय की अवमानना के समान थे, लेकिन कुछ को छोड़कर, अन्य का नोटिस नहीं लिया गया। इनमें से कुछ में उन्होंने महाभियोग की धमकी देकर न्यायाधीशों को डराने की भी कोशिश की। वह इस तरह से लिखने के आदी हैं। जब हमने न्यायिक प्रशासन में शुचिता और दक्षता लाने के लिए उनके द्वारा पहने गए धर्मयुद्ध के पर्दे को भेदा, तो उपरोक्त तथ्यों से हमें पता चला कि उनकी गतिविधि कोई धर्मयुद्ध नहीं है, जैसा कि वे कहते हैं, बल्कि अदालतों को बदनाम करने के लिए है।

33. मामलों की बात करें तो हमने जांच की है: सिरदर्द के मामले पूरी तरह से। प्रतिवादी ने 4 नवंबर 1978 को लिखे अपने पत्र के उस अंश का उल्लेख किया है जिसके आधार पर आपराधिक मूल क्रमांक 7 1979 में स्थापित किये गये नियमों को बहुत ही अहानिकर बताया गया है। इस हिस्से की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि ये वैसा नहीं है जैसा उन्होंने बताया है. निकाले गए भाग को 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसे निर्णय के पैरा 2 में पुन: प्रस्तुत किया गया है, इसे संदर्भ से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। भाग 'ए' से ठीक पहले वाला वाक्य प्रतिवादी के इरादे और उद्देश्यों का संकेत प्रदान करता है: -

> “25 अक्टूबर, 1978 को किसी भी पंजीकृत पत्र में फिर से। मैंने अपनी प्रार्थना दोहराई, आग्रह किया कि अधिमानतः इसे पांच माननीय न्यायाधीशों द्वारा सुना जाना चाहिए और यदि संभव नहीं है, तो कम से कम तीन माननीय न्यायाधीशों द्वारा। आख़िरकार, इसे 3 नवंबर यानी कल के लिए सूचीबद्ध किया गया।”

इसी संदर्भ में जब अवमाननाकर्ता चाहता था कि मामले को पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए तो उसने इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ

अपनी क्रोधित भावनाओं को व्यक्त किया। यह बेंचों के गठन के मामले में मुख्य न्यायाधीश के अधिकार के संबंध में प्रतिवादी द्वारा किया गया एक चालाकीपूर्ण उपहास था।

भाग 'बी' में अवमाननाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश को संविधान के उल्लंघनकर्ता के रूप में संबोधित किया, और इसके लिए अपने सचिव श्री एसपी पार्टी को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य बताया। यह मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ एक संदिग्ध तरीके से की गई निरंकुश आलोचना का एक रूप है, ताकि उनके पुनरीक्षण, जो कि सामान्य था, को पूर्ण पीठ द्वारा सुनने का एक महत्वपूर्ण गौरव प्राप्त करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। पूर्ण पीठ के समक्ष अपने पुनरीक्षण को सूचीबद्ध करने की प्रतिवादी की अपनी मांग पर कायम रहने का इरादा ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसे सार्वजनिक रूप से बताना चाहता था, जैसा कि उस पीठ की धारणा थी जिसने उसे 18 दिसंबर, 1980 को अवमानना के लिए दोषी ठहराया था। अदालत का सार्वजनिक महत्व हासिल करने के लिए, कि उनके व्यक्तित्व की भागीदारी के कारण मामले की सुनवाई पूर्ण पीठ द्वारा की गई थी।

न्यायालय की स्थापना के प्रशासन में, जो कि न्याय प्रशासन का एक आवश्यक अंग है, मुख्य न्यायाधीश को बार-बार संविधान का उल्लंघनकर्ता कहना मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के प्रति अवमानना प्रदर्शित करना ही है। ये आरोप प्रतिवादी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को संविधान का उल्लंघनकर्ता बताकर उनके खिलाफ अपनाए गए बदनामी भरे अभियान का हिस्सा हैं। इस प्रकार, भाग 'ए.' और इस पत्र का 'बी', जो भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को संबोधित था, अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई) के दायरे में आता है क्योंकि इसका निंदनीय प्रभाव है।

34. 1979 के सीओसी नंबर 8 से, भाग 'ए' को फैसले के पैरा 4 में पुन: प्रस्तुत किया गया है। यह एक संदर्भ में था जैसा कि ठीक पिछले वाक्य में दर्शाया गया है कि श्री केएस थापर, वकील ने 1978 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444 में प्रतिवादी ने अपना उपस्थिति ज्ञापन वापस ले लिया था, जो

उसने श्री एसके सेठी, आईपीएस की ओर से दायर किया था और इसके कारण प्रतिवादी को अपने स्थान पर वापस जाना पड़ा। निराशा के कारण जब उन्हें वापस जाना पड़ा, तो उन्होंने इस हिस्से में उच्च न्यायालय कार्यालय के खिलाफ असंयमित भाषा का प्रयोग किया। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश को संबोधित इस पत्र का भाग 'ए' उस तरीके से लिखा गया था; इसे नजरअंदाज करने की जरूरत है। असंयमित भाषा का प्रत्येक प्रयोग न्यायालय की अवमानना नहीं है। इसलिए, हम प्रतिवादी को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी ठहराने के लिए इस पत्र के भाग 'ए' पर ध्यान नहीं देते हैं।

इस पत्र का भाग 'बी' भाग 'ए' के समान संदर्भ में है। इस मामले में प्रतिवादी ने अपने पुनरीक्षण के लिए पूर्ण पीठ का गठन न करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य बताया था। इसी प्रभाव के लिए 1979 के सीओसी संख्या 9 का भाग 'ए' और 1979 के सीओसी संख्या 11 का भाग 'ए' है, जहां पूर्ण पीठ गठित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की झूठी प्रतिष्ठा को दोहराया गया था और यह भी कहा गया था कि बंसी लाल और सुखदेव पार्षद की मदद के लिए पूर्ण पीठ का गठन नहीं किया जा रहा था। इन भागों में मामला वही है और यह एक अनुचित आरोप है। प्रतिवादी जैसा व्यक्ति, जो कभी विधायक था और जिसके पास अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमेबाजी और शिकायतों का व्यापक अनुभव है, उसे पता होना चाहिए कि पूर्ण पीठों का गठन किसी व्यक्तित्व की साधारण भागीदारी पर नहीं किया जाता है, बल्कि केवल कानूनी भागीदारी के कारण किया जाता है। और जटिल प्रश्न. मुख्य न्यायाधीश को यह बताना कि उनके द्वारा झूठी प्रतिष्ठा के तहत काम करते हुए और कुछ लोगों की मदद करने के विचार से पूर्ण पीठ का गठन नहीं किया जा रहा है, पीठों के गठन के मामले में मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर आक्षेप है। हमने इस सवाल पर खुद को संबोधित किया कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की क्या झूठी प्रतिष्ठा हो सकती है और खोजबीन करने पर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए, यह भाग इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके न्यायिक कार्यों के निर्वहन में

गलत मकसद बताकर बदनाम करने के समान है।

इस पत्र के भाग 'ग' से पहले का वाक्य व्यंग्यात्मक है। यह वाक्य इस प्रकार है: -

> "फिर यदि आप व्यक्तियों के बारे में चिंता नहीं करते हैं और इतने कठोर हैं कि कॉमरेड के बार-बार अनुरोध आपको एक बेंच गठित करने के लिए मनाने में विफल रहे हैं, तो उन्हें –

यह वाक्य इस निर्णय के पैराग्राफ 4 में निकाले गए भाग के साथ निरंतर है और उस भाग के पूछताछ के संकेत के साथ समाप्त होता है। जब इस भाग को निरन्तरता से पढ़ा जाता है तो इसका संकेत मिलता है। यह व्यंग्य स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इस पत्र में की गई व्यंग्यात्मक टिप्पणी केवल पूर्ण पीठ के गठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए है।

इस पत्र के भाग 'डी' और 'एफ' स्वभाषी हैं। भाग 'डी' में, पिछले भाग की तरह, मुख्य न्यायाधीश को संविधान का उल्लंघनकर्ता बताया गया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को विवेकहीन, राष्ट्रविरोधी और संविधान का उल्लंघन करने वाला बताया है. उन्होंने पहले की तरह फिर से अपने पुनरीक्षण की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ के गठन की मांग की। ये फिर से न्यायिक प्रशासन के कार्यों में मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि अंश में बताया गया है, गृह मंत्रालय को शिकायत करके उन्होंने न्यायालय की गरिमा को भी गिराने का प्रयास किया।

भाग 'ई' को इसके ठीक पहले वाले वाक्य की निरंतरता में पढ़ा जाना चाहिए, जो इस प्रकार है: -

> "अब मुझे आपका ध्यान क्रिमिनल लॉ जर्नल, 1973, पृष्ठ 1106 में प्रकाशित फैसले की ओर आकर्षित करना है, जिसमें यह स्पष्ट है कि मुख्य न्यायाधीश श्री हरबंस सिंह ने एक व्यक्ति और वह भी भ्रष्ट न्यायिक अधिकारी के हितों की रक्षा की और मुझे खड़ा कर दिया। अवमानना कार्यवाही का सामना करने के लिए डॉक।"

इस संदर्भ में, उन्होंने इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) हरबंस सिंह और डीके महाजन के आचरण की आलोचना की। डीके महाजन, सीजे के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा एक संदर्भ फिर से सुझाव देता है कि प्रतिवादी किसी भी एजेंसी द्वारा उसके खिलाफ पारित किसी भी आदेश को बर्दाश्त नहीं करता है, चाहे वह कोई भी हो। हालाँकि 1973 क्रिमिनल एलजे 1106 में रिपोर्ट किए गए मामले में डीके महाजन, सीजे ने प्रतिवादी के बारे में कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उन्होंने उन्हें (महाजन, सीजे को) न्यायिक रिकॉर्ड को गढ़ने वाला कहकर बदनाम किया। यह भाग 1979 के सीओसी क्रमांक 11 के भाग 'ए' के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के मन में न्यायाधीशों के प्रति दुर्भावना उत्पन्न हो गई है, जिनके साथ वह सहज महसूस नहीं करता था। इसी आशय के लिए हरबंस सिंह, सीजे के संबंध में 1979 के सीओसीपी संख्या 11 में 24 जनवरी, 1979 के पत्र का भाग 'ए' है, ये इस न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की न्यायिक और प्रशासनिक निष्ठा पर जानबूझकर और सोच-समझकर किए गए हमले हैं। काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और प्रतिवादी को उनकी छवि खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रतिवादी का आचरण, फिर से अधिनियम की धारा 2(सी)(1) के दायरे में आता है।

35. 1979 के सीओसी संख्या 9 का भाग 'ए', पैरा 5 (सुप्रा) में पुनरुत्पादित, 1979 के सीओसी संख्या 8 में माना गया है। भाग 'बी' में इस पत्र के भाग 'ए' में आरोप के संदर्भ में प्रतिवादी ने अपने आरोपों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की मंशा पर संदेह किया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य न्यायाधीश की मंशा ठीक नहीं थी क्योंकि झूठी प्रतिष्ठा के कारण बंसी लाल और सुखदेव पार्षद की मदद के लिए पूर्ण पीठ का गठन नहीं किया गया था। यह फिर से मुख्य न्यायाधीश पर उनके न्यायिक कार्यों के संबंध में दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाया गया है। यह भी आपराधिक अवमानना है।

36. 1979 के सीओसी संख्या 10 में भाग 'ए' अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफलता के कारण हताशा के माध्यम से लिखा गया प्रतीत होता है।

इन पत्रों में पहली बार आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग प्रतिवादी की कलम से छूट गया। हालाँकि यह भाषा अनौचित्य की ओर झुकी हुई है, लेकिन अधिनियम की धारा 2(सी) के किसी भी भाग की शरारत के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ जारी नियम को खारिज किया जाता है।

37. 1979 के सीओसी संख्या 11 के भाग 'ए' को 1979 के सीओसी संख्या 8-के साथ माना गया है। इस पत्र के भाग 'बी' में, प्रतिवादी ने इस न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों हरबंस सिंह और डीके महाजन के भ्रष्ट इरादों को जिम्मेदार ठहराया। श्री आरएल लांबा की मदद करें। उन्होंने आगे लिखा है कि सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर उन्होंने उनकी मदद की. हालाँकि इस तरह के घृणित आरोपों का औचित्य शायद ही कोई बचाव है, लेकिन हमें प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया कोई भी मामला नहीं मिला है जहाँ से इन टिप्पणियों का कोई औचित्य सामने आ सके। प्रतिवादी ने इस न्यायालय के न्यायाधीशों को बदनाम करने की अपनी शैली में, चाहे वे वर्तमान हों या पूर्व, आरोप लगाए हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। 1973 क्रिमिनल एलजे 1106 (सुप्रा) में प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत को इस न्यायालय के एक न्यायाधीश को न सौंपने के संबंध में बेंच की टिप्पणी, जो कमल में न्यायालयों का निरीक्षण करने गए थे, किसी भी उद्देश्य को प्रतिबिंबित नहीं करती है। हरबंस सिंह, सीजे प्रतिवादी ने उन टिप्पणियों से लाभ उठाने की कोशिश की, जो, हमारे विचार में, बिंदु से परे थे, जहां तक भाग 'ए' में आरोप लगाने के औचित्य का संबंध है। ये आरोप अपमानजनक हैं और उन न्यायाधीशों को बदनाम करने के इरादे से लगाए गए हैं।

37-ए. भाग 'बी' में प्रतिवादी ने 24 जनवरी, 1979 के अपने पत्र में श्री आरएल लांबा की टिप्पणियों को हटाने के संबंध में एससी मित्तल, जे. के आदेश की एक प्रति की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है। इसका मतलब यह है कि जब प्रतिवादी ने इस पत्र के भाग 'सी' में एससी मित्तल, जे. के खिलाफ आरोप लगाए, तो उन्होंने विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश नहीं देखा था। वह पीसी जैन, जे की कोर्ट में मिली जानकारी पर ही काम कर रहे थे। कोर्ट ऑन

इट्स ओन मोशन बनाम कॉमरेड राम पियारा (केएस तिवाना, जे.), इससे पता चलता है कि प्रतिवादी ने आदेश की सामग्री को सत्यापित किए बिना या सच्चाई जाने बिना, इस न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश, यानी एससी मित्तल, जे. के प्रशासन पर इतना भद्दा हमला किया। इस तरह के अनियंत्रित हमले को उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं होने दिया जा सकता है। प्रतिवादी इस कृत्य के लिए अदालत की अवमानना के कानून की पकड़ से दायित्व से बच नहीं सकता क्योंकि यह अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई) में निहित है।

38. 1979 के आपराधिक मूल अवमानना मामले संख्या 7 से 11 की सुनवाई एसएस सिद्धू और हरबंस लाल, जेजे की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी। प्रतिवादी ने आपराधिक विविध याचिका संख्या 2700, दिनांक 19 मई, 1979 प्रस्तुत की, जो उस पीठ के समक्ष आई। इस आपराधिक विविध में, प्रतिवादी ने इस पीठ का गठन करने वाले विद्वान न्यायाधीशों पर ऐसे आदेश पारित करने में शर्म महसूस करने का आरोप लगाया, जो उनके विचार में, उनकी ओर से गलतियों को सुधारने के समान था। इसका उल्लेख फैसले के पहले भाग में किया गया है, जहां सभी मामलों में प्रतिवादी को एक समग्र नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनके द्वारा इंगित करने पर, बेंच के आदेशों के तहत अलग-अलग नोटिस भेजे गए थे। इसी संदर्भ में उन्होंने कार्यालय द्वारा की गई गलती को सुधारने में शर्म महसूस करने का जिक्र किया था, जिसे उन्होंने बेंच की चूक के रूप में चित्रित करने की कोशिश की थी। उन्होंने उस याचिका में आगे कहा कि वह जानना चाहते हैं कि उन्हें पांच पत्रों के आधार पर पांच नोटिस क्यों भेजे गए, जबकि 1971 में उन्हें पांच पत्रों के आधार पर अवमानना का केवल एक नोटिस जारी किया गया था। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने फैसले के पैरा 9 में पुन: प्रस्तुत आपराधिक विविध संख्या 2700 में भाग 'ए' लिखा। इसके लिए, इस आपराधिक विविध से यह भाग, 1979 के सीओसी नंबर 18 की शुरुआत की गई थी। आपत्तिजनक मामले वाले प्रत्येक व्यक्तिगत संचार को एक स्वतंत्र विषय वस्तु होना चाहिए? सूचना। पीठ की प्रतिक्रिया पर

प्रतिवादी ने अपमानजनक भाषा में प्रतिकूल टिप्पणी की। एक आरोप यह भी लगाया गया कि मुख्य न्यायाधीश की भनक कानूनी बाध्यताओं व अन्य से ज्यादा महत्व रखती है. न्यायालयों की गरिमा बनाए रखने के लिए स्वस्थ मिसालें। यह भी व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की गई थी कि कानून का शासन एक निष्पक्ष, निडर और स्पष्ट न्यायपालिका के अस्तित्व को पहले से मानता है। किसी न्यायाधीश पर न्यायिक मामलों में किसी के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाने से ज्यादा भयावह कुछ नहीं हो सकता। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीठ निर्भीक या स्पष्टवादी ढंग से नहीं, बल्कि मुख्य न्यायाधीश की इच्छा के अनुरूप कार्य कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी फिर से चाहता था कि 1971 में उसके खिलाफ शुरू किए गए एक मामले को बराबर करके, पांच मामलों के लिए एक नोटिस देकर उस बेंच के समक्ष चीजें अपने तरीके से की जाएं। नोटिस जारी करना एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए न्यायाधीशों। अगर एक समय ऐसा सोचा जाता, उस स्थिति की अत्यावश्यकताओं के अनुसार, केवल एक नोटिस ही पर्याप्त हो सकता है, जो कि एक ही अवमाननाकर्ता द्वारा अपराध दोहराए जाने की स्थिति में सभी समय के लिए नोटिसों की संख्या को केवल एक तक सीमित करने के लिए न्यायालय को बाध्य नहीं करता है। यदि उनकी स्थिति को स्वीकार किया जाना था, तो इस तरह के पुनरावर्तक? अपराधों के लिए केवल एक ही नोटिस देना अच्छी स्थिति में होगा, भले ही असंख्य संचार में आपत्तिजनक मामले हों या एक ही प्रकार के एक से अधिक प्रकाशन हों। नोटिसों को केवल एक तक सीमित रखने के अपने उद्देश्य को विफल होते देख, उन्होंने न्यायाधीशों पर दुर्भावनापूर्ण भाषा में आरोप लगाया कि उन्हें उम्मीद से अधिक रोशनी मिल रही है और वे मुख्य न्यायाधीश के प्रभाव में काम कर रहे हैं। न्यायाधीशों के आचरण और आदेशों के लिए प्रतिवादी द्वारा भाषा के प्रयोग पर अंकुश लगाना होगा। जब वह चीजों को अपने इच्छित तरीके से प्राप्त करने के अपने उद्देश्य में विफल हो जाता है, तो उसे न्यायाधीशों को बदनाम करने का सिलसिला जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस पत्र के भाग 'ए' की भाषा

न्यायालय की न्यायिक कार्यप्रणाली के लिए अपमानजनक है और इसका इस्तेमाल जानबूझकर अदालत को बदनाम करने और न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के लिए किया गया है। इस मामले को लिखित रूप में प्रतिवादी का यह कृत्य अधिनियम की धारा 2(सी)(आई) के अंतर्गत आता है।

39. 2 अप्रैल, 1979 के उनके संचार में, जिसके आधार पर 1979 की सीओसी संख्या 19 शुरू की गई थी, फैसले के पैरा 10 में दो अंश पुनः प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके लिए नोटिस जारी किया गया था। पहले में प्रतिवादी ने कहा कि चूंकि मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, अन्य न्यायाधीशों ने सोचा कि उनकी (मुख्य न्यायाधीश की) उस मामले में किसी न किसी में रुचि है, यानी 1978 की आपराधिक संशोधन संख्या 444 में 1979 के सीओसी संख्या 8 के भाग 'ए' में प्रतिवादी द्वारा इसी प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया था और मुख्य न्यायाधीश को संशोधन में पार्टियों में रुचि के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए समान अर्थ देने में सक्षम है। 1979 के सीओसी संख्या 8 में दिए गए उन्हीं कारणों के आधार पर, हम इस परिच्छेद को उसी प्रभाव के बारे में मानते हैं।

दूसरे भाग में अवमाननाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश ने 'न्यायिक मानकों' की प्रतिष्ठा को कम किया है। उन्होंने विधायक रामलाल वाधवा के मामले का भी जिक्र किया, जिसमें देरी हो रही थी। चूंकि वह चाहते थे कि उनके आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 444, 1978 को एक विशेष संख्या में न्यायाधीशों के समक्ष एक विशेष तरीके से सूचीबद्ध किया जाए, जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं किया गया, उन्होंने प्रतिष्ठा को कम करने के लिए उनके (मुख्य न्यायाधीश) खिलाफ निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाए। और न्यायिक मानक। हमारे विचार से यह मामला बिल्कुल अलग है। यदि मुख्य न्यायाधीश ने, प्रतिवादी से प्राप्त संचार में अशोभनीय और अवमाननापूर्ण भाषा के दबाव में, मामले को पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का कार्य किया होता, तो यह हो सकता था।

किसी ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश एक दबंग वादी द्वारा अशोभनीय भाषा के प्रयोग के दबाव में झुक गये हैं। उस स्थिति में इसे न्यायिक मानकों में गिरावट के रूप में लिया जा सकता है। हालाँकि, अब इस मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि एक वादी के नखरों पर ध्यान न देकर, मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा काम किया है जिससे उनके न्यायिक कार्यों के निर्वहन में उनकी ईमानदारी पर सवाल उठ सकते हैं। इस भाग के लेखक होने के नाते, श्री राम पियारा प्रतिवादी का कृत्य अधिनियम की धारा 2(सी)(i) के विभिन्न

खंडों के अंतर्गत आता है क्योंकि उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ झूठी और दुर्भावनापूर्ण भाषा का आरोप लगाकर न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश की है।

40. संचार का एक हिस्सा दिनांक 25 अप्रैल, 1979, जिसके आधार पर 1979 के सीओसी संख्या 20 में नोटिस जारी किया गया था, निर्णय के पैरा 11 में पुन: प्रस्तुत किया गया है। उस संदर्भ का पहला भाग एससी मित्तल, जे के आदेश को संदर्भित करता है, जिसमें प्रशासनिक पक्ष पर श्री आरएल लांबा की फ़ाइल से टिप्पणियों को हटा दिया गया था, उन्हें अवैध, असंवैधानिक और बहुत खराब मिसाल कायम करने वाला बताया गया था। उन्होंने आगे लिखा कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इनका इस्तेमाल न्याय की शुचिता को प्रभावित कर सकता है. हालाँकि इस हिस्से में प्रतिवादी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा बहुत सुखद नहीं है, लेकिन हमें अदालत की अवमानना के लिए उसे दोषी ठहराने के लिए इस हिस्से का इस्तेमाल करना उचित नहीं लगता।

एससी मिफाल, जे के समक्ष अपने पुनरीक्षण की सूची का उल्लेख करते हुए, जब माननीय न्यायाधीश ने पहले ही इसे सुनने से इनकार कर दिया था, उन्होंने इस न्यायालय के उप रजिस्ट्रार पर आरोप लगाया, जिसका नाम 1973 आपराधिक एलजे 1106 (सुप्रा) में आया था। उन्होंने अपने पुनरीक्षण का इतिहास बताते हुए कहा कि हो सकता है कि उस मामले में कोई शरारत की गयी हो। उन्होंने यह भी कहा कि जब मुख्य न्यायाधीश की मंशा ईमानदार नहीं होती है तो ऐसी शरारतें आम होती हैं और यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्व की तरह, वर्तमान उप रजिस्ट्रार ने मुख्य न्यायाधीश की इच्छा को लागू किया होगा। इसमें उन्होंने एक बार फिर बिना किसी आधार के मुख्य न्यायाधीश के मन में उनके प्रति संदेह जताया है. जब उन्होंने यह टिप्पणी की तो वह अपने मामले की लिस्टिंग का जिक्र कर रहे थे। जैसा कि हमने पहले देखा है, प्रतिवादी बिना किसी आधार के अपने चारों ओर प्रेत देख रहा था। उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं रखा और चीजों की सही परिप्रेक्ष्य में सराहना नहीं कर रहे थे क्योंकि वह इस विचार से ग्रस्त थे कि उनके पुनरीक्षण की सुनवाई पूर्ण पीठ द्वारा की जानी चाहिए। प्रशासन के हित के प्रति मुख्य न्यायाधीश की ईमानदारी के बारे में खुद को व्यक्त करने में

प्रतिवादी का आचरण उसकी ओर से एक गलत कृत्य है और उसे बदनाम करने के लिए जानबूझकर किया गया है।

फैसले के पैरा 11 में उद्धृत तीसरे अनुच्छेद का मामला दूसरों से अलग नहीं है। इसमें उन्होंने SC पर आरोप लगाया है मितल, जे. पर अपने पुनरीक्षण, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बंसी लाल एक पक्ष थे, को सुनने से इनकार करके न्याय प्रदान करने में दोहरे मानकों का उपयोग करने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में उनके (बंसी लाल) द्वारा दायर जमानत के लिए एक आवेदन पर सुनवाई की। प्रतिवादी ने पूरे समय कहा कि एससी मितल, जे. द्वारा पुनरीक्षण नहीं सुना गया, क्योंकि श्री बंसी लाल उसमें एक पक्ष थे। हमें सीआरएल के रिकॉर्ड मिल गए। 1978 के संशोधन संख्या 444 को पेश किया गया और पाया गया कि 5 मई, 1978 को एससी मितल के रीडर जे. ने फ़ाइल के साथ एक पर्ची लगाई थी कि मामले को किसी अन्य एकल पीठ के समक्ष तय किया जाए। जैसा कि इस न्यायालय की प्रथा है, मामले को किसी अन्य पीठ को भेजने के लिए कोई कारण नहीं दिया जाना चाहिए और वास्तव में नहीं दिया गया था। हम इस न्यायालय के न्यायाधीश की तुलना किसी वादी से नहीं कर सकते, विशेष रूप से उस प्रकार के प्रतिवादी को रीडर के नोट के समर्थन या विरोध में सामग्री ढूंढनी होती है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब उसके बाद मामला मेरे सामने सूचीबद्ध किया गया, तो श्री राम पियारा प्रतिवादी मेरे सामने इस अनुरोध के साथ उपस्थित हुए कि मैं मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। मैं उस अनुरोध पर सहमत हो गया। मेरे रीडर ने वैसा ही नोट डाला जैसा एससी मितल के रीडर जे ने किया था। बाद में, मुख्य न्यायाधीश, - प्रतिवादी के उत्तर में अपने नोट को पुन: प्रस्तुत करते हुए, चाहते थे कि मैं मामले का फैसला करूं और इसे फिर से मेरे सामने सूचीबद्ध किया गया था। अब प्रतिवादी मेरे खिलाफ कुछ बयान लेकर आया है। यह उदाहरण राम पियारा प्रतिवादी के खिलाफ मामले में पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के लिए कोई सामग्री लाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों पर उनके द्वारा लगाए गए दोहरे मानकों के आरोपों की उचित सराहना के लिए दिया गया है। एससी मितल, जे के खिलाफ दोहरे मापदंड का आरोप शरारतपूर्ण होने के साथ-साथ दुर्भावनापूर्ण भी है और इस तरह के बयान अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई) के दायरे में आते हैं और इस पर गंभीरता से ध्यान देने

की आवश्यकता है।

41. 17 नवंबर 1978 को क्रिमिनल रिवीजन संख्या 444 सन् 1978 के फैसले के बाद यह तारीख ली गयी. पत्र से ही, राम पियारा प्रतिवादी ने मुझे एक पत्र लिखा था क्योंकि मैंने उस संशोधन का निर्णय लिया था। इस फैसले के पैरा 12 में 1979 के सीओसी नंबर 21 के पत्र से उद्धृत पहले दो अंशों में, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मुझे प्रभावित करने और उनके प्रभाव में उस फैसले को देने के लिए मुझ पर आरोप लगाए हैं। दोनों आरोप सिर्फ जजों को बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। इस स्तर पर इस मामले के रिकॉर्ड से थोड़ा सा विचलन अनावश्यक नहीं हो सकता है। यदि हम 1978 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444 के फैसले का संदर्भ लें, जिसका संदर्भ अक्सर प्रतिवादी द्वारा किया गया है, तो उस फैसले में यह पाया जा सकता है कि राम पियारा प्रतिवादी ने उस मामले में गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं की। उन्होंने केवल उस पुनरीक्षण याचिका को पूर्ण पीठ को सौंपने का तर्क दिया। उस संशोधन को पूर्ण पीठ को सौंपने की अपनी मांग के समर्थन में वह जो कुछ भी कहना चाहते थे, कहने के बाद, वह निश्चित रूप से अनुमति के साथ, योग्यता पर किसी भी बहस को संबोधित किए बिना, कोर्ट रूम से चले गए। उनकी मदद और सहायता के बिना मामले का फैसला किया गया। यह संदर्भ केवल इस उद्देश्य के लिए दिया गया है कि वह कानून या नियमों के औचित्य या पालन का कम से कम ध्यान रखते हुए अपने तरीके से कार्य करता है। उनका एकमात्र उद्देश्य पूर्ण पीठ के समक्ष पुनरीक्षण को सूचीबद्ध कराना था। यदि इसे सूचीबद्ध किया गया होता, तो ऐसी कोई भी घटना नहीं होती जिसके कारण उनके खिलाफ 11 मामले शुरू किए गए। प्रतिवादी ने अपने उत्तर में यह भी कहा: "सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए मामला एक है और 1978 के आपराधिक संशोधन संख्या 444 से उत्पन्न हुआ है।" लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों के इस्तेमाल के लिए कानून और प्रक्रिया को दरकिनार किया जा सकता है, जो अपनी अनुचित और अस्थिर मांगों के पूरा न होने पर न्यायाधीशों के चरित्र हनन का सहारा लेते हैं, जो उनकी बात नहीं मानते। अपने आपराधिक पुनरीक्षण को पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराने में असफल रहने से क्रोधित होकर, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और मुझ पर दुर्भावनापूर्ण हमला किया।

पत्र से निकाले गए आखिरी हिस्से में उन्होंने न्यायपालिका के मानकों को गिराने के लिए झूठे आरोप लगाकर एक बार फिर मुख्य न्यायाधीश को बदनाम किया। इसी तरह की टिप्पणियों पर हमने पहले भी इस फैसले के पहले पैराग्राफ में विचार किया है और इसे अधिनियम के तहत अपराध पाया गया है।

इसलिए, ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम पाते हैं कि 1979 के सीओसी नंबर 21 में प्रतिवादी का कार्य और आचरण अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई) में परिभाषित 'आपराधिक अवमानना' के बराबर है।

42. उनकी लेटेरे दिनांक 28 मई, 79, 1979, जो कि 1979 की सीओसी संख्या 22 के आधार पर है, प्रतिवादी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर गंदी, निंदनीय और निंदनीय भाषा का उपयोग करके शालीनता और औचित्य की सभी सीमाएं पार कर ली हैं। न्यायाधीश, जिनके पास इन मामलों से निपटने का अवसर था। उन्होंने उनके फैसलों और आदेशों को प्रेरित बताते हुए उन पर महाभियोग चलाने की भी धमकी दी है. मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित भाग 'ए' में उन्होंने कहा कि उनके हाथों में न्याय की छड़ी सीधी नहीं थी और न ही न्याय का तराजू संतुलित था। प्रतिवादी ने यह नहीं बताया है कि क्या मुख्य न्यायाधीश को कभी उसके किसी मामले पर न्यायिक निर्णय लेने का अवसर मिला था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को केवल इसलिए परेशान करने की कोशिश की है क्योंकि उनकी पुनरीक्षण याचिका पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं थी, जिसकी कानून और नियम अनुमति नहीं देते थे। शुरुआत करने की यही एकमात्र बात थी जिस पर प्रतिवादी को बुरा लगा और उसके लिए यह कहना उचित नहीं है कि न्याय की छड़ी सीधी नहीं थी या न्याय का तराजू सीधा नहीं था।

एसएस संधवालिया, सीजे के हाथों में तैनात प्रतिवादी ने बाद में मुख्य न्यायाधीश को विभिन्न पत्र लिखकर मामलों को जटिल बनाने का प्रयास किया, जो निराधार आरोप लगाकर इन मामलों के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह सब प्रतिवादी ने कई पत्र लिखकर अपने पक्ष में अपने कार्यों को भुनाने के लिए किया था, जिस पर वह अब अपने बचाव के लिए भरोसा करना चाहता था। मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध इन शब्दों के प्रयोग का न तो कोई अवसर था और न ही कोई आधार। यह मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से

न्यायालय को बदनाम करने के लिए किया गया था।

इस पत्र के भाग 'बी' जैसा ही एक मामला हमने सीओसीजेपी के भाग 'बी' में निपटाया है। 1979 का क्रमांक 8 और न्यायालय की अवमानना का पाया गया। वहां दिए गए कारणों के अनुसार इसे भी अवमानना के अंतर्गत माना जाता है।

भाग 'सी' में प्रतिवादी ने एकल पीठ में मेरे समक्ष पुनरीक्षण सूचीबद्ध किए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने यह मामला मुझे सौंपा क्योंकि उन्हें लगा कि मैं श्री सुखदेव पार्षद और उनके (सुखदेव पार्षद की रुचि को मैं बेहतर ढंग से देख सकता था। मैं यहाँ यह भी जोड़ सकता हूँ कि श्री सुखदेव पार्षद कभी भी मेरे क्लास-फ़ेलो नहीं थे। यदि मैं पढ़ता था तो वह लॉ कॉलेज का समकालीन छात्र था, लेकिन मेरा क्लास-फ़ेलो नहीं था। इस भाग में, मामले को मेरे समक्ष सूचीबद्ध करने के पीछे मुख्य न्यायाधीश का मकसद बताया गया है क्योंकि मैंने एक बार इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। इस पत्र के भाग 'डी' में, उक्त संशोधन का जिक्र करते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि मुझे मुख्य न्यायाधीश का पालन करना था, न कि स्वस्थ उदाहरणों का और इस प्रकार मुझ पर मुख्य न्यायाधीश के प्रभाव में न्यायिक मामलों में काम करने का आरोप लगाया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने कई तरह के निराधार और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाए थे। इस तरह के आक्षेपों पर हमने पहले इस निर्णय में अन्य स्थानों पर भी विचार किया है और पाया है कि यह अवमानना है। उद्देश्यों का ऐसा झूठा आरोपण अधिनियम की धारा 2(सी)(आई) के दायरे में आता है।

इस पत्र के भाग 'डी' में मेरा जिक्र करते हुए उन्होंने 1978 के क्रिमिनल रिवीजन नंबर 444 में मेरे द्वारा दर्ज किए गए निर्णय के संदर्भ में लिखा कि मुझे एसएस संधावालिया, सीजे का पालन करना था, न कि स्वस्थ उदाहरणों का। इसी तरह के आक्षेप पर हमने इस फैसले के पहले भाग में चर्चा की है और इसे 'आपराधिक अवमानना' माना है। उन्हीं कारणों को दोहराकर हम पहले से ही लंबे फैसले की मात्रा को और बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए, भाग 'डी' में कही गई बातें अधिनियम की धारा 2(सी) में परिभाषित 'आपराधिक अवमानना' के समान हैं।

इस पत्र के भाग 'ई' में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, वह प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना है, जबकि उन्होंने फैसले का वर्णन किया था। 1978 के आपराधिक संशोधन संख्या 444 में "दुर्भावना, चालाकी, बल्कि बेईमानी से भरा हुआ" के रूप में। इसलिए, उन्होंने कहा कि मैं कदाचार का दोषी था, जिसके लिए संसद नहीं तो सर्वशक्तिमान द्वारा महाभियोग की आवश्यकता थी। भाग 'जे' में इसी तरह के मामले में, उन्होंने एसएस सिद्धू और हरबंस लाल, जेजे को महाभियोग की धमकी दी; उन्होंने उनके आदेश को 'न केवल मूर्खता बल्कि चालाकी पर भी पारित करने का वर्णन किया, क्योंकि वे एसएस संधवालिया को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते।' किसी वादी द्वारा उसे उजागर करने से बड़ा कदाचार नहीं हो सकता। किसी निर्णय या न्यायिक कार्यवाही में न्यायाधीशों के आदेश को भ्रष्ट और धूर्तता और दुर्भावना पर आधारित बताने के बजाय आपराधिक अवमानना का दंड। हमने एसएस सिद्धू और हरबंस लाल, जेजे की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों का अध्ययन किया है। इन दोनों न्यायाधीशों द्वारा गठित 'पीठ ने शुरू में 1979 के सीओसी संख्या 7 से 11 में प्रतिवादी को नोटिस जारी किया था। जब उनके द्वारा पांच मामलों को निपटाया जा रहा था, तो प्रतिवादी ने 1979 की आपराधिक विविध संख्या 2700 में कुछ आधारहीन आरोप लगाते हुए दायर किया था। उन्हें फिर से. उन्होंने इस आपराधिक विविध याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन राम पियारा प्रतिवादी को अदालत की अवमानना के लिए एक और नोटिस जारी किया और 1979 के सीओसी संख्या 18 की शुरुआत की। 1979 के इस आपराधिक विविध संख्या 2700 में वे अंश, जो अवमाननापूर्ण हैं और उन पर चर्चा की गई है इस फैसले के पैरा 38 में प्रथम दृष्टया यह अदालत की अवमानना है। प्रतिवादी के आचरण और ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों के सारांश से यह स्पष्ट है कि जब भी इस न्यायालय की पीठें उसके तर्क से सहमत नहीं हुईं, तो वह उन पर दुर्भावनापूर्ण हमले करने के लिए आगे आया। जब उन्होंने 1979 के अपने आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 444 पर गुण-दोष के आधार पर बहस नहीं की और इसे खारिज कर दिया गया, तो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और मेरे खिलाफ आरोप लगाए। इस संचार के भाग 'एफ' में उन्होंने हमें इस न्यायालय में ट्रक रखने वाले भ्रष्टों के प्रति स्नेह के कारण अन्यथा कार्य करने का उल्लेख किया है। भाग 'जी' में उन्होंने फिर से हम दोनों का

जिक्र करते हुए लिखा कि उनके क्रिमिनल रिवीजन पर निर्णय लेने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। इस हिस्से में हमला सबसे मुखर और निंदनीय है जब उन्होंने लिखा कि “यह मेरी सुविचारित राय है, अगर मैं आप दोनों को यह लिखने का साहस करूँ कि आप सबसे भ्रष्ट, पक्षपातपूर्ण, अन्यायी हैं, तो आप बहुत नाराज़ महसूस करेंगे। ”। इस पत्र के भाग 'टी' के एक भाग में, प्रतिवादी राम पियारा ने लिखा है: "वास्तव में आपने खुद को दोनों, यानी बंसी लाल और सुखदेव पार्षद की तुलना में अधिक भ्रष्ट, अधिक बेईमान साबित किया है।" प्रतिवादी, जो अपने पत्रों में इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा, अदालत में विविध आवेदनों और किसी भी मामले को अपने तरीके से तय करने के समान व्यवहार के बावजूद अपने प्रयासों में असफल रहा, उसने इस पैराग्राफ में उल्लिखित उद्देश्यों को अपने तरीके से आरोपित किया। इस न्यायालय के न्यायाधीश. कानून और न्याय के नियमों के सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं देते थे। न्यायाधीशों द्वारा उस तरह से निर्णय लेना जिस तरह से प्रतिवादी चाहता था और वह न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेशों या उसके खिलाफ दर्ज किए गए निर्णयों को स्वीकार नहीं करता था। फैसले के पिछले भाग में, राम पियारा प्रतिवादी के आचरण और रवैये पर पर्याप्त विस्तार से ध्यान दिया गया था, जो उसे न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक, निंदनीय और यहां तक कि अपमानजनक भाषा का उपयोग करके अदालत की अवमानना करने के एक आदतन अपराधी के रूप में दर्शाता है। उन्हें डराने के लिए. इस उप-अनुच्छेद में चर्चा किए गए इन भागों की भाषा का उद्देश्य न्यायालय को बदनाम करना और न्यायिक निर्णयों के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डालना है, अर्थात उसके पास लंबित न्यायालय की अवमानना के मामले हैं। ऐसा इस विचार से किया गया है कि न्यायाधीशों के मन में घिनौने हमलों से डर पैदा हो जाए, ताकि वे उसे जारी किए गए नोटिसों से मुक्त कर दें या कम से कम उसके मामलों से दूर रहें। हरबंस दल और सीएस तिवाना, जे.जे. की डिवीजन बेंच द्वारा उनके मामले की एक दिन की सुनवाई के बाद, उन्होंने 18 सितंबर, 1980 को हरबंस लाल, जे. को डाक द्वारा एक पत्र भेजा, जिसमें हरबंस लाल, जे. के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। परिणाम यह हुआ कि, 20 सितंबर, 1980 के आदेशों के तहत, हरबंस लाल, जे. ने मामले को किसी अन्य बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। जब

इस खंडपीठ ने इन मामलों की सुनवाई शुरू की, तो प्रतिवादी 26 नवंबर, 1980 को अनुपस्थित हो गया, जब मामले की एक दिन की सुनवाई हो चुकी थी। उन्हें विशेष रूप से अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने निर्देश की अवहेलना की और खुद को अनुपस्थित कर लिया। जब इस बेंच द्वारा उनकी उपस्थिति के लिए वारंट जारी किए गए, तो उन्होंने हमारे खिलाफ आरोप लगाकर अपना प्रदर्शन दोहराना शुरू कर दिया, ताकि यह बेंच उन मामलों की सुनवाई से भी बच सके, जो दो साल से अधिक समय से लंबित थे। यह अपने मामलों के निर्णय से बचने के लिए प्रतिवादी की कार्यप्रणाली है। भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाने में प्रतिवादी का आचरण इन उद्देश्यों के साथ था और यह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। प्रतिवादी ने न्यायाधीशों को महाभियोग की धमकी देकर डराने में भी संकोच नहीं किया, जैसा कि इस पत्र के भाग 'ई' और 'एफ' से स्पष्ट है। यह न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप से कम नहीं है।

इस पत्र के भाग 'के' में, प्रतिवादी ने फिर से संदर्भों के माध्यम से न्यायाधीशों के कृत्यों को भ्रष्ट और न्यायपालिका को प्रदूषित करने वाले उनके कार्यों का वर्णन किया है। इससे एक बार फिर न्यायालय की बदनामी हुई है।

भाग 'एल' में प्रतिवादी ने फिर से मुख्य न्यायाधीश को संविधान का उल्लंघन करने वाला और भ्रष्ट आचरण को प्रोत्साहित करने वाला बताया है। हम पहले ही इसी तरह के आरोपों पर चर्चा कर चुके हैं। फैसले के पहले भाग में पाया गया कि यह आपराधिक अवमानना है। ये अधिनियम की धारा 2(सी)(i) और 2(सी)(iii) के दायरे में आते हैं।'

43. 1979 के सीओसी नंबर 23 के मामले में, प्रतिवादी ने 14 जून, 1979 को एसएस सिद्धू और हरबंस लाल, जेजे को पत्र भेजा, जब वे उसके खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे थे। पत्र के भाग 'ए' में, मुख्य न्यायाधीश पर फिर से प्रतिवादी को हतोत्साहित करने के बुरे इरादे रखने का आरोप लगाया गया। मुख्य न्यायाधीश को फिर से श्री सतपाल पार्टी के लिए संविधान का उल्लंघनकर्ता कहा गया, जो प्रतिवादी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश को शराब की आपूर्ति कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश के संविधान का उल्लंघनकर्ता होने के बारे में इन टिप्पणियों के संबंध में, हम पहले ही मान चुके हैं कि यह अदालत

की अवमानना है और हमें इन सभी आरोपों पर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य एक ही है, एक ही इतिहास और एक ही पृष्ठभूमि है। प्रतिवादी ने मुख्य न्यायाधीश पर उनका मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें हतोत्साहित करने की पहल कैसे की या ऐसा करने से मुख्य न्यायाधीश को क्या लाभ होगा। यह "प्रतिवादी स्वयं था, जिसने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ निंदा का अभियान शुरू कर दिया था जब उनका मामला पूर्ण पीठ के समक्ष उनकी इच्छा के अनुसार सूचीबद्ध नहीं किया गया था। मुख्य न्यायाधीश पर दबाव बनाने के लिए, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के आदेशों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय के कर्मचारियों की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना तथा अन्य सभी प्रकार के आरोप लगाना, जिनकी वह कल्पना कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश का कार्य केवल न्यायालय की गरिमा तथा उसकी छवि की रक्षा करना है, जिसे प्रतिवादी लगातार करता रहता है। बदनाम करने की कोशिश की गई और उन्होंने उन पत्रों को एक डिवीजन बेंच के समक्ष रखा, जिसने उन्हें (प्रतिवादी) नोटिस जारी किया। जैसा कि हमने पाया, मुख्य न्यायाधीश ने उनके और अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ प्रतिवादी के गुस्से की जांच कराने के लिए कदम उठाने के अलावा कुछ नहीं किया। न्यायिक रूप से यह जानने के लिए कि क्या ये कानून का उल्लंघन है। प्रतिवादी ने अपने लिए एक स्थिति बनाई और इस स्थिति से मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ उन्हें हतोत्साहित करने के बुरे इरादों के लिए निराधार आरोप लगाना शुरू कर दिया। क्या प्रतिवादी चाहता है कि मुख्य न्यायाधीश को उसे इस न्यायालय और इसके न्यायाधीशों के खिलाफ अपना घृणित अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश के सचिव श्री एसपी पार्टी द्वारा शराब की आपूर्ति के बारे में लगाए गए आरोप अपमानजनक हैं और इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के व्यक्तित्व को बदनाम करने और उनका बचाव करने के इरादे से लगाए गए हैं। यह भाग फिर से सुरक्षित रूप से अधिनियम की धारा 2(सी)(i) के अंतर्गत आता है।

इस पत्र के भाग 'बी' में उन्होंने बेंच द्वारा जानबूझकर श्री एससी मोहंता की उपस्थिति दर्ज नहीं करने के बारे में लिखा है। तत्कालीन महाधिवक्ता, हरियाणा जिन्हें न्यायालय की सहायता करनी थी। इस पर कोई ध्यान देने के लिए यह

संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हालाँकि, इस भाग का दूसरा भाग अवमाननापूर्ण है जब प्रतिवादी ने लिखा कि दस्तावेजों और हलफनामों की आपूर्ति न करने में बेंच ने शालीनता, कानून और न्याय की बहुत कम परवाह की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सनक की अधिक परवाह की।

भाग 'सी' में उन्होंने फिर आरोप लगाया है कि पीठ को मुख्य न्यायाधीश से विशेष निर्देश प्राप्त थे। मुख्य न्यायाधीश को अपना फैसला सौंपने के लिए पीठ के खिलाफ लगाए गए ये बेबुनियाद आरोप गलत और अवमाननापूर्ण हैं। ये बेबुनियाद और बेबुनियाद आरोप "तब लगाए गए जब एक बेंच में ये दो न्यायाधीश प्रतिवादी के खिलाफ मामलों से निपट रहे थे। कार्यवाही के ऐसे चरण में ऐसी भाषा का उपयोग जैसा कि पिछले पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं हो सकता है न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का एक उद्देश्य, ताकि ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों के प्रभाव में बेंच उसके खिलाफ मामलों को आगे न बढ़ा सके। ये टिप्पणियाँ धारा 2 (सी) (आई), 2 (सी) और अधिनियम के (ii) और 2(सी)(iii) की पकड़ के भीतर विफल हो जाती हैं।

इस पत्र के भाग 'डी' में, उन्होंने 1979 के सीओसी संख्या 22 में भाग 'ई' और 'जी' की तरह निर्णय और आदेश पारित करने में अभद्रता के आरोपों को फिर से दोहराया। हमें इसे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है और न्यायिक क्षमता में न्यायिक मामलों के निर्णय में न्यायाधीशों पर बेईमानी का आरोप लगाने के संबंध में भी इसी तरह के कारण हैं। 1979 के सीओसी संख्या 22 में उपरोक्त भागों में दर्ज कारणों से, हम पाते हैं कि इस पत्र में प्रतिवादी के ये लेख धारा 2(सी)(i), 2(सी)(ii) और 2 के दायरे में आते हैं। (सी)(iii) अधिनियम के। इस पत्र के भाग 'ई' में उन्होंने न केवल एसएस सिद्धू और हरबंस लाल , जेजे को महाभियोग की धमकी दी, बल्कि आगे कहा: -

" .....क्योंकि आप मुख्य न्यायाधीश को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठा सकते श्री एसएस संधावालिया, आप सेवानिवृत्ति के करीब हैं, जबकि उन्हें कई वर्षों तक पद पर बने रहना है, यदि उनके दुर्व्यवहार और कदाचार के कारण महाभियोग नहीं चलाया जाता है और इसलिए, आप अपने बेटों और रिश्तेदारों की ओर देख रहे हैं, जो आपके और आपके कारण पैसा कमा रहे हैं

काश कि अगर मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए, तो वह आपके रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के पैसे कमाने की राह में बाधा बन जाएंगे।"

यह पीठ के खिलाफ बहुत ही बेतुका आरोप है। जैसा कि पहले भी देखा जा चुका है, इसे केवल न्यायाधीशों को भयभीत करने के उद्देश्य से ही समतल किया गया है झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। महाभियोग का खतरा फिर से धारा 2(c)(i), 2(c)(ii) और 2(c) (iii) के संचालन के क्षेत्र में आ गया।

हमें इस पत्र के भाग 'एफ' पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम फैसले के पहले भाग में ऐसे मामलों पर चर्चा कर चुके हैं।

44. बहस के दौरान प्रतिवादी श्री राम पियारा ने कहा कि जब उनका पुनरीक्षण पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया तो उन्हें मुख्य न्यायाधीश को संचार भेजना पड़ा। हाई कोर्ट की गलती के कारण 5/6 बार चंडीगढ़ से करनाल वापस जाना पड़ा। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें वित्तीय नुकसान और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ा, जब चंडीगढ़ पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि मेमो वापस लेने, विरोधी पक्ष के वकील द्वारा या किसी अन्य कारण से उनका पुनरीक्षण नहीं सुना जा सका। यह सच है कि उन्हें ऐसी कोई असुविधा हुई होगी, लेकिन न्यायिक कार्यवाही में ऐसी चीजें अपरिहार्य हैं। ऐसी घटना, यदि घटित होती है, तो असुविधाग्रस्त व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय के न्यायाधीशों पर आरोप लगाने का कारण नहीं मिलता है। चाहे कोई व्यक्ति इच्छुक वादी हो या मुकदमा करने के लिए मजबूर किया गया हो, उसे मुकदमों की पैरवी में कुछ हद तक वित्तीय हानि और शारीरिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। खर्चों और असुविधाओं के प्रभाव में, उसे न्यायालय को बदनाम करने या बदनाम करने और उसकी अवमानना करने के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता। जब कोई व्यक्ति मुकदमेबाजी करता है, तो उसे न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए और जब तक वे कायम रहते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। हमें इस प्रकार की मानसिक मनोवृत्ति का कोई औचित्य नहीं मिलता, जैसा कि प्रतिवादी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ***श्री सी.के. दफ्तरी और अन्य*** **बनाम** ***श्री ओ. पी. गुप्ता और***

अन्य[3]**,** में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ को लाभ के साथ संदर्भित किया जा सकता है जिसमें यह देखा गया कि ऐसे मामलों में औचित्य अवमानना के लिए बचाव नहीं है।

45. हमें प्रतिवादी राम पियारा मिला है, जो दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और अवमाननापूर्ण पत्राचार लिखने और इस न्यायालय के न्यायाधीशों पर भद्दे हमले करने में इस प्रकार के व्यवहार का आदी है। इस फैसले के पैराग्राफ 1 में उद्धृत अनुच्छेद में 1973 आपराधिक एलजे 1106 में रिपोर्ट किए गए मामले में एचआर सोढ़ी, जे. द्वारा उनके मानसिक ढांचे का सही आकलन किया गया था। वह उसके खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर हो, के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण तरीके से खुल जाता है। उन्होंने, जैसा कि फैसले के पहले भाग में कहा गया है, राजनेताओं, अखबार के संपादकों, मजिस्ट्रेटों, इस न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य लोगों को नहीं बख्शा।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अशोभनीय आलोचना और भद्दी टिप्पणियों से। हालाँकि उन्होंने खुद को एक योद्धा के रूप में वर्णित करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ एक नियमित शिकायतकर्ता हैं। मामलों की विस्तार से चर्चा करते हुए, प्रतिवादी राम पियारा के इतिहास, मुकदमेबाजी और अवमानना मामलों में उनकी भूमिका और अनुभव की पृष्ठभूमि में, हम उन्हें अदालत की अवमानना के अपराध का दोषी पाते हैं। इस न्यायालय के सेवानिवृत्त और सेवारत न्यायाधीशों पर उनके न्यायिक कृत्यों में अपमानजनक हमलों से उचित न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे जैसे देश में इस तरह के हमलों से न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कम होने का अपरिहार्य प्रभाव पड़ता है। यदि लोगों का विश्वास चला जाता है, तो न्याय प्रशासन को निश्चित रूप से नुकसान होता है। इसलिए, हम नीचे दिए गए तरीके से इन मामलों में प्रतिवादी राम पियारा को दोषी ठहराते हैं।

46. 1979 के सीओसी नंबर 7 में, 24 नवंबर 1978 के पत्र में लिखने के लिए, फैसले के पैरा 3 में पुन: प्रस्तुत किए गए अंश और फैसले के पैरा 3बी में चर्चा की गई, हम धारा 2(सी)(i) के तहत प्रतिवादी राम पियारा को

[3] 1971 (1) एस. सी. मामले 626।

दोषी ठहराते हैं।

अधिनियम से 1979 के सीओसी नंबर 8 में, 2 दिसंबर, 1978 के पत्र में लिखे गए अंशों के लिए, एम पैरा 4 को पुन: प्रस्तुत किया गया और फैसले के पैरा 34 में चर्चा की गई, हम राम पियारा, प्रतिवादी को धारा 2 (सी) (i) के तहत दोषी ठहराते हैं।

अधिनियम का 1979 के सीओसी नंबर 9 में, 8 दिसंबर, 1978 के पत्र के लिए, पैरा 5 में पुन: प्रस्तुत किए गए और फैसले के पैरा 35 में चर्चा किए गए अंशों के लेखक होने के नाते, हम प्रतिवादी राम पियारा को धारा 2 (सी)(i) के तहत दोषी ठहराते हैं।

अधिनियम का 1979 के सीओसी नंबर 11 में, 24 जनवरी 1979 को लिखे गए पत्र के अंशों के लिए, पैरा 7 में पुन: प्रस्तुत किया गया और फैसले के पैरा 37 में चर्चा की गई, हम धारा 2 (सी) (आई) के तहत प्रतिवादी राम पियारा को दोषी ठहराते हैं।

अधिनियम का 1979 के सीओसी नंबर 18 में, 1979 के आपराधिक विविध नंबर 2700 में अंश लिखने के लिए, पैरा 9 में पुन: प्रस्तुत किया गया और फैसले के पैरा 38 में चर्चा की गई, हम राम पियारा, प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 2 (सी) (आई) के तहत दोषी ठहराते हैं।

1979 के सीओसी संख्या 19 में, 2 अप्रैल 1979 के पत्र में अंश लिखने के लिए, जिसे पैरा 10 में पुन: प्रस्तुत किया गया है और निर्णय के पैरा 39 में चर्चा की गई है, हम प्रतिवादी फैम पियारा को धारा के तहत अदालत की अवमानना करने के लिए दोषी ठहराते हैं।

अधिनियम के 2(सी)(i), 2(सी)(ii) और 2(सी)(iii), 25 अप्रैल, 1979 के पत्र में अंश लिखने के लिए 1979 के सीओसी संख्या 20 में, जिसे पैरा 11 में पुन: प्रस्तुत किया गया है और निर्णय के पैरा 40 में चर्चा की गई है, हम प्रतिवादी राम पियारा को धारा 2(ग) (i) के तहत अदालत की अवमानना करने के लिए दोषी ठहराते हैं।

अधिनियम का 1979 के सीओसी संख्या 21 में, 29 मई 1979 के पत्र में अंश लिखने के लिए, पैरा 12 में पुन: प्रस्तुत किया गया और निर्णय के

पैरा 41 में चर्चा की गई, हम प्रतिवादी राम पियारा को धारा 2 (सी) (i) के तहत अदालत की अवमानना करने के लिए दोषी ठहराते हैं।

अधिनियम के 1979 के सीओसी संख्या 22 में, 28 मई 1979 को पत्र लिखने और उसके अंशों को पैरा 13 में पुन: प्रस्तुत करने और निर्णय के पैरा 42 में चर्चा करने के लिए, हम प्रतिवादी राम पियारा को धारा 2 के तहत अदालत की अवमानना करने के लिए दोषी ठहराते हैं।

अधिनियम के (सी)(i), 2(सी)(ii) और 2(सी)(iii) 1979 के सीओसी संख्या 23 में, 14 जून 1979 के पत्र के अंशों के लिए, जिन्हें पैरा 14 में उद्धृत किया गया है और निर्णय के पैरा 43 में चर्चा की गई है, हम राम पियारा, प्रतिवादी को दोषी ठहराते हैं या धारा 2 के तहत अदालत की अवमानना करते हैं।

47. हम यहां उल्लेख कर सकते हैं कि यह हममें से किसी की या न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की गरिमा की किसी अतिरंजित धारणा के कारण नहीं था कि हमने इस न्यायालय की अवमानना के लिए प्रतिवादी राम पियारा के खिलाफ कार्रवाई की, बल्कि इसलिए कि यह इस न्यायालय पर लगाया गया है। ब्रेवि मनु को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने से रोकने का कर्तव्य। ऐसे मामलों में सज़ा नहीं दी जाती जैसा कि ब्रैडकांता मिशम के मामले (सुप्रा) में देखा गया है, या तो संपूर्ण अदालत या अदालत के व्यक्तिगत न्यायाधीशों को हमले की पुनरावृत्ति से बचाने के उद्देश्य से, बल्कि जनता की रक्षा करने के लिए, और विशेष रूप से जो लोग स्वेच्छा से या मजबूरी से न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, यदि न्यायालय का प्राधिकार क्षीण होता है तो वे उत्पात मचाएंगे। प्रतिवादी जानबूझकर न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहा है और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अदालत को बदनाम कर रहा है। उनका उद्देश्य समाज में अपनी नकारात्मक भूमिका के लिए सार्वजनिक रूप से कुख्यात होना भी हो सकता है। इसलिए उससे सख्ती से निपटने की जरूरत है।

48. अब सवाल आता है कि प्रतिवादी राम पियारा को क्या सजा दी जाए। 16 अप्रैल, 1979 को 1979 के सीओसी संख्या 7 से 11 में उनकी उपस्थिति के बाद, उन्होंने एक बार भी पश्चाताप का कोई संकेत प्रदर्शित नहीं

किया है। दूसरी ओर, उन्होंने इस न्यायालय की लगातार अवमानना पर गंभीर रूप धारण किये और दिये विभिन्न पीठों का अपमान। इस न्यायालय में अपने निंदनीय लेखन को जारी रखते हुए संचार भेजकर, उन्होंने न्यायालय की अवमानना, यानी सीओसी के छह और नोटिस की शुरुआत अर्जित की। 1979 की संख्या 18 से 23 तक, जब उन्होंने पिछले मामले में नोटिस के परिणामस्वरूप उपस्थिति दर्ज की थी। के दौरान. सुनवाई के दौरान उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और उनकी अदालत के आदेशों के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करके अदालत की अवमानना की। इनमें से एक नोटिस डिस्चार्ज हो गया और एक में उन्हें दोषी करार दिया गया. इन मामलों को पहले फैसले के दौरान संदर्भित किया गया है। उन्होंने आपराधिक विविध आवेदनों की एक नियमित धारा बनाए रखी, जिसमें उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं बख्शा, हालांकि इस अदालत में उनके बारे में कुछ भी कहने का अवसर नहीं था। उन्होंने बहस के दौरान हमारे और इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस अदालत के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया और इसके लिए हमें उन्हें निष्पक्ष सुनवाई और बचाव का उचित अवसर देने के नाम पर दो दिनों तक कष्ट सहना पड़ा, जो हमने उन्हें दिया था। प्रतिवादी के इस आचरण के लिए, हमने एक समय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 को लागू करने पर विचार किया था, जो सजा देने में उच्च न्यायालय की शक्तियों को सीमित नहीं करता है, जो कि रिकॉर्ड अदालत है। हमने खुद को केवल इसलिए रोका ताकि प्रतिवादी आश्चर्यचकित होने और पूर्वाग्रह की दलील न दे, हालांकि यह संविधान के उस प्रावधान के तहत निपटने के लिए एक उपयुक्त मामला था। प्रतिवादी ने कटु, तिरस्कारपूर्ण और निंदनीय आरोपों से अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा है। उनका मामला अमरीक सिंह[4] के मामले के समान है, जहां अदालत की अवमानना के एक कृत्य पर, अवमाननाकर्ता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यूनतम छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत को बदनाम करने के ऐसे कृत्य, जैसा कि सीके डेफ्ट्री के मामले (सुप्फा) के मामले में देखा गया, हमेशा उच्च

[4] (1971) 1 एस. सी. डब्ल्यू. आर. 581।

न्यायालय को बदनाम करने और उसके अधिकार को कम करने और अदालतों में लोगों के विश्वास को हिलाने का कारण बनता है। जब प्रतिवादी पियारा जैसे व्यक्ति, जो कभी विधायक रहा है और इस अदालत और अधीनस्थ अदालतों में मुकदमेबाजी कर रहा है, द्वारा इस तरह की बात का सहारा लिया जाता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उनका इरादा अदालतों के लिए भय का माहौल पैदा करने का है, जिस पर रोक लगाने की जरूरत है। हम चिंता के साथ देखते हैं कि जब इस अदालत में प्रतिवादी का रवैया यह है, जिसे हमने पहले देखा है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वह अधीनस्थ अदालतों के सामने क्या स्थिति पैदा कर सकता है, जहां, अपने स्वयं के दावे के अनुसार, वह अक्सर उपस्थित होता है। कानून के दायरे में आने वाली उसकी गतिविधियों पर कोई प्रीमियम नहीं लगाया जा सकता। हमें इन मामलों में नरमी बरतने का कोई कारण नहीं मिलता है, जहां प्रतिवादी का कार्य और आचरण जानबूझकर किया गया है और कब दो साल से अधिक समय के दौरान इस अदालत में अपनी कई प्रस्तुतियों के दौरान, क्षमा याचना करने और पश्चाताप करने के बजाय वह हमेशा स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करता रहा और उसी अवसर पर उसने वास्तव में ऐसा किया भी। अदालत में दायर प्रत्येक विविध आवेदन के साथ, उन्होंने अवमानना का एक नया कार्य किया। हालाँकि इन 11 मामलों की सामग्री, उन हिस्सों के अलावा, जिन पर हमने विचार किया है, अदालत की अधिक गंभीर अवमानना के समान है, लेकिन हमने उस पर विचार नहीं किया है क्योंकि नोटिस जारी करने वाली पीठ ने पहले ही उन हिस्सों को चिह्नित कर लिया था। हालाँकि, हम उन हिस्सों से प्रभावित नहीं हैं, जिन्हें हमने अपने फैसले में ध्यान में नहीं रखा है। हमारे विचार में, प्रतिवादी उस पर सुधारात्मक प्रभाव डालने के लिए कड़ी सजा का हकदार है।

49. इन टिप्पणियों के साथ, हम 1979 के सीओसी नंबर 7, 8, 9, 11, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में प्रतिवादी राम पियारा को अधिनियम की धारा 12 के तहत छह महीने के साधारण कारावास की सजा देते हैं। प्रत्येक मामला। प्रतिवादी पर रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रत्येक मामले में 1,000/- रु. जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक मामले में दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। प्रतिवादी राम पियारा पर सजा का निवारक प्रभाव डालने के लिए, हम इन सजाओं को लगातार चलाने का निर्देश देते हैं।

हमने प्रत्येक मामले में पत्रों के प्रत्येक भाग के लिए अवमाननाकर्ता को अलग से दोषी नहीं ठहराया है, बल्कि समग्र आधार पर आदेश पारित किए हैं। हमने उन मामलों में भी कोई अलग सजा पारित नहीं की है जिनमें हमने उसे अधिनियम की धारा 2 (सी) (ii) और 2 (सी) (iii) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है। तदनुसार आदेश दिया गया।

50. फैसले से अलग होने से पहले हम एक नये मोड़ का जिक्र कर सकते हैं। हमें इस दिन आदेश सुनने के लिए प्रतिवादी को उपस्थित रहने की आवश्यकता थी। इसी बीच 13 अगस्त, 1981 को हमें प्रतिवादी द्वारा 12 अगस्त, 1981 की पोस्ट के माध्यम से एक संचार प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने हम पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहीं और परामर्श लेने के लिए निर्णय तैयार करने में समय लेने का आरोप लगाया। पत्र का एक उद्धरण पुन: प्रस्तुत है -

> "मैंने सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला कि यह 7वां भी नहीं हो सकता, 7वां शुक्रवार है। और आपके चेहरे से, मैं अपनी बुद्धि और अनुभव के कारण, यह धारणा बना सकता हूं कि शनिवार और रविवार को छुट्टियां होने के कारण सीजे श्री संधवालिया से परामर्श करने के लिए शांत सोच का लाभ उठाया जाएगा और वह जरूरत पड़ने पर सीजे श्री वाईवी चंद्रचूड़ से परामर्श कर सकते हैं। ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरे रिट 6308/80 को खारिज करने के उनके आदेश 30 मई, 1981 को हिंदुस्तान टाइम्स में छपे मेरे पत्र के दो पैरा पढ़ने के साथ-साथ तर्कों में भी शामिल था, जहां योग्य एससी रजिस्ट्री की भूमिका के साथ-साथ इस न्यायालय की रजिस्ट्री की अयोग्य भूमिका भी मेरी टिप्पणियों में सामने आई है कि ये रजिस्ट्रियां मुख्य न्यायाधीशों की बंदियां हैं और "सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट" के लिखित आदेशों या नियमों का उल्लंघन करने की सुरक्षित रूप से अनदेखी कर सकती हैं।

51. इस प्रकार के व्यक्ति से हमें निपटना पड़ा। इस पत्र से जो कुछ निकलता है वह एक ऐसा मामला है जिस पर भविष्य में हमारे विचार की प्रतीक्षा हो सकती है।

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

अवंतिका
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा